नई दिल्ली । गुरुवार, 23 जुलाई, 2026
आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083
वर्ष :12, अंक :198 / मूल्य 3.00 रुपए । पृष्ठ 12

दैनिक
विश्व केसरी
सिर्फ पत्रकारिता...
नई दिल्ली संस्करण
vishwakesari.com
@vishwakesariTV
@vishwakesari
vishwa_kesari_official
आर. एन. आई. संख्या डीईएलएच आईएन/2015/61415

@ खेल वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप : अनाहत और आर्यवीर... @ विचार छात्र आंदोलन : मुद्दों से भटकती बहस और भविष्य की... @ व्यापार भारत में विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड क्षमता 57,443 मेगावाट...

जंतर-मंतर पर पुलिस और छात्र फिर हुए आमने-सामने

सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

DHARMENDRA PRADHAN MUST RESIGN SCRAP NTA
क्रांति कॉर्नर KRANTI CORNER
SF
HUNGER STRIKE
क्रांति कॉर्नर • KRANTI CORNER

एजेंसी ■ नई दिल्ली

दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुधवार रात छात्रों और पुलिस में फिर झड़प हो गई। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे।

इससे पहले 20 जुलाई को सीजेपी के संसद मार्च के दौरान झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारी संसद गेट के करीब पहुंच गए थे। उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया था। अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी का शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर करीब 2000 जवानों को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से एयरलिफ्ट कर लाया गया।

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कारण 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। हालांकि शाम को सभी स्टेशन खोल दिए गए। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आरएएफ के एक जवान पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारी आरएएफ जवान के साथ मारपीट करते, आरएएफ के वाहन पर पथराव करते और उसमें तोड़फोड़ किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में स्टूडेंट्स से मारपीट के मामले में अर्जी पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- मारपीट के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं।

अन्ना हजारे का पीएम को पत्र, कहा- मंत्री के इस्तीफे से सरकार कमजोर नहीं होगी

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पुलिस की कार्रवाई बेहद परेशान करने वाली थी। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार कमजोर नहीं होगी, बल्कि इससे दूसरे मंत्रियों को जवाबदेही के बारे में एक मजबूत संदेश जाएगा और कामकाज में सुधार होगा। युवा परीक्षा के पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित हैं।

सेंसेक्स 715 अंक फिसला

एजेंसी ■ मुंबई

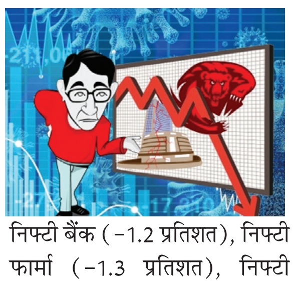

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों के चलते हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को लगातार तीसरे सत्र में भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। इस बीच घरेलू बाजार के प्रमुख बेंचमार्कों में करीब 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

बाजार बंद होने के समय सेंसेक्स 715.06 प्रतिशत या 0.92 प्रतिशत गिरकर 76,755.05 पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी50 191.45 अंक या 0.79 प्रतिशत गिरकर 23,996.25 पर आ गया।

निफ्टी 50 इंडेक्स में इंडिगो, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, एसबीआई, मैक्स हेल्थ और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली, तो वहीं, बजाज-ऑटो, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर और इटरनल के शेयर सबसे ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप क्रमशः 1.09 प्रतिशत और 1.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टरवार देखें तो, निफ्टी मीडिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा, जिसमें 2.68 प्रतिशत की गिरावट आई, इसके बाद निफ्टी रियल्टी (-2.6 प्रतिशत), निफ्टी पीएसयू बैंक (-1.8 प्रतिशत), निफ्टी प्राइवेट बैंक (-1.4 प्रतिशत), निफ्टी आईटी (-1.5 प्रतिशत), निफ्टी बैंक (-1.2 प्रतिशत), निफ्टी फार्मा (-1.3 प्रतिशत), निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (-0.86 प्रतिशत), निफ्टी इंफ्रा (-0.85 प्रतिशत), निफ्टी ऑयल एंड गैस (-0.6 प्रतिशत), निफ्टी मेटल (-0.48 प्रतिशत) और निफ्टी एनर्जी (-0.3 प्रतिशत) में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं, निफ्टी एफएमसीजी 0.65 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष लाभ कमाने वाला सेक्टर बनकर उभरा, इसके बाद निफ्टी ऑटो 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यह बेंचमार्क सूचकांकों के लिए लगातार तीसरा दिन था जब उनमें गिरावट दर्ज की गई। लगातार तीन सत्रों में सेंसेक्स में लगभग 1,400 अंकों यानी करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि एनएसई निफ्टी 50 में 300 अंकों से ज्यादा यानी 1.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एक मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि पिछले आठ कारोबारी सत्रों से निफ्टी डेली चार्ट पर 24,367 से 24,000 के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा था।

आज इस दायरे से निर्णायक ब्रेकडाउन देखने को मिला और इंडेक्स ने एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनाई। साथ ही, निफ्टी अपनी प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल गया।

'छात्रों के मुद्दों का राजनीतिकरण न हो': जेपी नड्डा

एजेंसी ■ नई दिल्ली

नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर चल रहे प्रदर्शन और सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छात्रों के प्रदर्शन का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इसका राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। छात्रों की समस्या पर गहनता से चर्चा की जरूरत है।

भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे राहुल गांधी ने संसद में प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान उन्होंने 150 पेपर लीक की बात कही। यह जांच का विषय है और सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए सभी बातों का जवाब सरकार देगी। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और कर्नाटक में पेपर लीक हुए। यहां कांग्रेस और विपक्षी दलों के समर्थन वाली सरकारें हैं। ये तो कुछ ही मामले हैं।

उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप चयनात्मक क्यों हैं? आपने 'इंडिया अलायंस' की सरकारों के बारे में चर्चा क्यों नहीं की? आपने उन्हें अलग क्यों रखा? इसी से साफ पता चलता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित, शिक्षा में सुधार और छात्रों को न्याय दिलाना नहीं है। आप छात्रों के मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं।

जेपी नड्डा ने आगे कहा कि यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। यह गंभीर मामला है। मैंने कुछ जगहों के नाम गिनाए, जहां पेपर लीक हुआ और वहां विपक्षी दलों की सरकार है। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के लिए सबसे अच्छी जगह संसद है। सदन में इस पर चर्चा हो, गहनता से चर्चा हो और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर भी चर्चा हो। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मामला सरकार के सामने आने के बाद हमने क्या किया, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य सरकारों को भी इस मामले को कैसे देखना चाहिए और किन बिंदुओं पर चर्चा करके समाधान निकालना जरूरी है, जिससे छात्रों के साथ अन्याय न हो, इस पर भी विचार होना चाहिए। सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और इसे गंभीरता से लिया है।

जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष समय तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि समाधान पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के बाद हमें ठोस नीति लेकर आना चाहिए। बच्चे देश का भविष्य हैं। देश के भविष्य की चिंता करना हमारी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि मिलकर इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाए।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह एक जिम्मेदार सरकार है, जो हमेशा सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार रहती है।

नीट मामला : राहुल गांधी ने रखीं तीन मांगें, 'शिक्षा मंत्री का इस्तीफा

जिम्मेदारों पर कार्रवाई और सरकार से माफी की अपील

एजेंसी ■ नई दिल्ली

नीट परीक्षा में पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं।

राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था ने गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों का भरोसा तोड़ा है और सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं के बावजूद शिक्षा मंत्रालय प्रभावी कदम नहीं उठा सका। राहुल ने कहा कि ऐसे में शिक्षा मंत्री को पद छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल निचले स्तर पर नहीं, बल्कि आदेश देने वाले और पूरे तंत्र के लिए जिम्मेदार लोगों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे मामले की अंतिम जवाबदेही सरकार के शीर्ष नेतृत्व की है। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और स्वीकार करें कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां रही हैं।

सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने के लिए तैयार

सरकार के सामने रखी शर्त

एजेंसी ■ नई दिल्ली

नई दिल्ली । शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा पेपर लीक मामलों में जवाबदेही और छात्रों के हितों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का स्पष्ट लिखित आश्वासन मांगा है। उन्होंने कहा कि ऐसा आश्वासन मिलने पर ही वह अनशन समाप्त करने पर विचार करेंगे। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक खुला पत्र साझा किया, जिसे उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी. नड्डा और केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के नाम संबोधित किया गया है। उन्होंने पत्र में बताया कि दोनों मंत्री मंगलवार रात अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। वांगचुक ने लिखा कि मुलाकात के दौरान मंत्रियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। इनमें परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर संसद में सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने जैसी मांगें शामिल हैं।

भारत की दृष्टिकोण से होर्मुज स्ट्रेट रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण

होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाया तो तेहरान के पुल और बिजली संयंत्र पर होगा हमला : ट्रंप

एजेंसी ■ वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी जहाज को निशाना बनाया गया, तो अमेरिका इसका जवाब ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर देगा।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, ' 'अब से जब भी इस्लामी गणराज्य ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी जहाज पर हमला करेगा, चाहे वह मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी अन्य हथियार या साधन से किया गया हो, तो अमेरिका एक पुल या बिजली संयंत्र को बम से नष्ट कर देगा। इसमें वे पुल या बिजली संयंत्र भी शामिल होंगे, जो राजधानी तेहरान के पास या उसके अंदर स्थित हैं।''

ट्रंप की चेतावनी में कई तरह के संभावित हमलों को शामिल किया गया है, जैसे मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या 'किसी भी अन्य उपकरण या हथियार' से किए गए हमले। राष्ट्रपति ने जवाबी कार्रवाई के तरीके के बारे में भी बताया और कहा कि हर ऐसे हमले के जवाब में अमेरिका 'एक पुल या बिजली संयंत्र' को निशाना बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ये ठिकाने तेहरान के अंदर या उसके आसपास स्थित हो सकते हैं।

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। इस रास्ते से दुनिया भर में भेजे जाने वाले कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।

भारत के लिए, जो अपनी कच्चे तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने पर माल ढुलाई का खर्च, ऊर्जा की कीमतें और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है।

एक दिन पहले मंगलवार को ही इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने एक बयान जारी कर कहा कि दो तेल टैंकरों को रोका गया है। ये टैंकर असुरक्षित रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। धमाकों के बाद टैंकरों में बड़े स्तर पर आग लग गई थी।

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका में जारी तनातनी के बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने मंगलवार को दावा किया कि अमेरिकी सेना ने दो तेल टैंकरों को गुमराह कर गलत रास्ते पर भेजा, जिस कारण उन्हें धमाकों का सामना करना पड़ा।

ई-रिक्शा की बैटरी के दुरुपयोग पर सरकार सख्त

तैयार किया साइबर सुरक्षा की मजबूती का ढांचा

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सरकार ने ई-रिक्शा बैटरी के अनधिकृत रिमोट कंट्रोल के लिए इन एप्लिकेशन के दुरुपयोग की रिपोर्टों का संज्ञान लिया है। इस क्रम में सरकार ने कुछ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लिकेशन को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने डिजिटल इकोसिस्टम में साइबर सुरक्षा और डिजिटल लचीलेपन को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत और समन्वित ढांचा तैयार किया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एकीकृत ढांचे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक शामिल है। उन्होंने कहा कि यह विभिन्न एजेंसियों के बीच साइबर सुरक्षा से संबंधित समन्वय सुनिश्चित करेगा।

बयान में कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70बी के तहत नामित भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आईसीटी) को साइबर घटनाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी बनाया गया है। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए साइबरस्पेस का विश्लेषण करता है। यह संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों और हितधारक एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करता है ताकि कार्रवाई की जा सके। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ए के प्रावधानों के तहत देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

बंगाल सरकार 25 जुलाई को कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी: सुवेंदु अधिकारी

विश्व केसरी ■

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के खजाने से होने वाली आय और व्यय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट 25 जुलाई को विधानसभा में पेश करेगी। इसके साथ ही यह सदन के चल रहे विस्तारित बजट सत्र का अंतिम दिन होगा।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार दोपहर सदन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। वे राज्य के गृह विभाग के बजट आवंटन पर चल रही चर्चा का जवाब दे रहे थे।

सीएजी रिपोर्ट पेश करने की घोषणा नए राज्य वित्त मंत्री, पत्रकार से राजनेता बने स्वपन दासगुप्ता ने पिछले महीने सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट प्रस्ताव पेश करते समय की थी।

अंततः, बुधवार को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कैग रिपोर्ट 25 जुलाई को सदन में पेश की जाएगी।

कैग रिपोर्ट पेश करने की तारीख की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ-साथ जवाबदेही का सवाल भी उठेगा। आप चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों न हों, अगर आपका नाम भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है, तो जांच जरूर होगी।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि सदन के अगले सत्र में कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी और उसी के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि कैग रिपोर्ट से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार उजागर होगा। चाहे मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों या कोई बड़ा नेता, कोई भी नहीं बचेगा और राज्य सरकार राज्यपाल से भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी देने की सिफारिश करेगी।

2020 में आए अम्फान चक्रवात के बाद राहत कार्यों में कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब अम्फान राहत के लिए दो किस्तों में 3,750 करोड़ रुपए दिए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्फान राहत कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। उस भ्रष्टाचार के मद्देनजर कैग की विशेष जांच कराई गई थी। उस जांच की रिपोर्ट न तो सार्वजनिक की गई और न ही सदन में पेश की गई। जांच रिपोर्ट में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

त्रिपुरा में सदियों पुरानी 'खारची पूजा' शुरू, इस बार थीम 'एक पेड़, मां के नाम'

विश्व केसरी ■

अगरतला। त्रिपुरा की सदियों पुरानी परंपराओं, भव्य धार्मिक अनुष्ठानों और रंगारंग आयोजनों के बीच ऐतिहासिक खारची पूजा बुधवार से शुरू हो गई। यह पूजा राज्य की पूर्व रियासत त्रिपुरा की पुरानी राजधानी पुरान हवेली (वर्तमान खयरपुर) में आयोजित की जा रही है, जो अगरतला से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अन्य गणमान्य लोगों के साथ सात दिवसीय मेले और खारची पूजा का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के सबसे श्रद्धेय और अनोखे धार्मिक आयोजनों में से एक में 14 देवताओं की एक साथ पूजा की जाती है।

देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के इस सप्ताहभर चलने वाले मेले और सदियों पुराने उत्सव में शामिल होने की उम्मीद है। यह आयोजन पारंपरिक रीति-रिवाजों, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच शुरू हुआ।

मान्यता है कि खारची पूजा और उससे जुड़ा मेला मनुष्यों के पापों के शुद्धिकरण का प्रतीक है। खारची पूजा एवं मेला समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रतन चक्रवर्ती ने कहा कि हर साल देशभर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस अनोखे उत्सव में शामिल होते हैं।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चक्रवर्ती ने उम्मीद जताई कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष से अधिक होगी।

उन्होंने बताया कि हरित त्रिपुरा के निर्माण के उद्देश्य से इस वर्ष खारची उत्सव की थीम 'एक पेड़, मां के नाम' रखी गई है। इसके तहत सात दिनों तक चलने वाले मेले में आने वाले लोगों को सरकारी पहल के तहत विभिन्न प्रजातियों के पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियों के कारण इस बार सीमा पार से आने वाले आगंतुकों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम रह सकती है।

मूल रूप से यह उत्सव त्रिपुरा की आदिवासी त्रिपुरी समुदाय की परंपरा से जुड़ा था, लेकिन समय के साथ यह सभी समुदायों और धर्मों के लोगों का उत्सव बन गया है। यह त्रिपुरा की सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समावेशिता की परंपरा को दर्शाता है।

पूरे आयोजन के दौरान रंग-बिरंगे पंडाल, आकर्षक रोशनी, धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक ढोल की धुनों से माहौल भक्तिमय बना रहता है।

खारची पूजा में कुल 14 देवताओं की पूजा की जाती है। इनमें शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय, गणेश, ब्रह्मा, अबधी (जल देवता), चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्रि (हिमालय) शामिल हैं।

इस पूजा की एक विशेष परंपरा पशु बलि भी है, जिसे श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।

भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति बढ़कर 39,055 पेटाजूल पहुंची, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी बड़ी छलांग: मंत्री

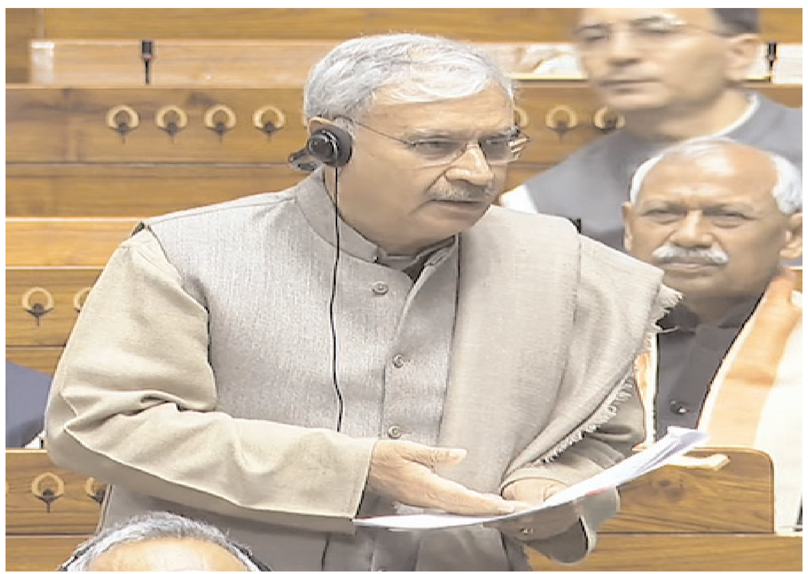

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई-टीपीईएस) वर्ष 2024-25 में बढ़कर 39,055 पेटाजूल हो गई है, जबकि 2023-24 में यह 37,936 पेटाजूल थी। यह जानकारी केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दी गई।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मार्च 2025 तक देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) क्षमता बढ़कर 47,04,043 मेगावाट आंकी गई है, जो एक साल पहले यानी 31 मार्च 2024 तक 21,09,655 मेगावाट थी।

उन्होंने बताया कि एक पेटाजूल ऊर्जा 1,0ख५ जूल (एक हजार लाख करोड़ जूल) या लगभग 278 गीगावाट-घंटे के बराबर होती है।

मंत्री ने कहा कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने आधिकारिक आंकड़ों के समय पर संग्रह और प्रकाशन के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित की है। नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) के तहत प्राथमिक आंकड़े अब कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) और ई-सिग्मा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जुटाए जाते हैं। इन प्लेटफॉर्म में इन-बिल्ट वैलिडेशन, रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग, एआई-आधारित चैटबॉट और बहुभाषी इंटरफेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से डेटा संग्रह के दौरान सटीकता बढ़ी है और सर्वेक्षण के आंकड़ों का रियल-टाइम में सत्यापन संभव हुआ है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से नियमित निरीक्षण और फील्ड स्टाफ को लगातार प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे आंकड़ों की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है।

राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इन सुधारों के कारण सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय पहले के 8-9 महीनों से घटकर 45 से 90 दिन रह गया है। अब वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 90-120 दिनों में, तिमाही रिपोर्ट 45-60 दिनों में और मासिक रिपोर्ट 15-30 दिनों के भीतर जारी की जा रही हैं।

कोलकाता : अग्निमित्रा पॉल ने कॉलेज स्ट्रीट का लिया जायजा, लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जैसा मेकओवर का प्लान

विश्व केसरी ■

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बुधवार को कोलकाता की सांस्कृतिक और शैक्षणिक जगह कॉलेज स्ट्रीट का निरीक्षण किया। यह दौरा भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के उस फैसले के तहत किया गया, जिसमें इस सड़क को लंदन की 'ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट' की तर्ज पर नया रूप देने का प्लान है।

मंत्री ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) की कमिश्नर स्मिता पांडे और दूसरे अधिकारियों के साथ पूरे कॉलेज स्ट्रीट इलाके का दौरा किया। इलाके का दौरा करते हुए उन्होंने पैदल चलने वालों और कुछ दुकानदारों से बात की।

प्लान के तहत, कॉलेज स्ट्रीट के एक हिस्से को 'नो-व्हीकल जोन' बनाया जाएगा। वहां किताबों की दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का भी प्लान है। किताब प्रेमी इलाके में साइकिल चला सकेंगे।

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि यह खास पहल अगली पीढ़ी को मोबाइल और डिजिटल दुनिया की लत से बाहर निकालने और उन्हें फिर से किताबों की ओर मोड़ने के लिए की जा रही है। कोई अपनी साइकिल लेकर नहीं आएगा। हर कोई यहां बने स्टैंड से साइकिल लेगा। जो लोग पैदल चलना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकेंगे। बुजुर्गों के लिए बैटरी से चलने वाली कारें होंगी।

मंत्री ने कहा, 'वहां किताबों की दुकानें, नोटबुक की दुकानें और बुक कैफे होंगे। यह एक 'नो-व्हीकल जोन' होगा। वहां सिर्फ साइकिलें चलेंगी और बुजुर्गों के लिए बैटरी से चलने वाली कारें होंगी। किताबें पढ़ने के लिए बेंच होंगी। वहां कोई शोर-शराबा नहीं होगा। हालांकि, हम अभी मुख्य कॉलेज स्ट्रीट को नहीं छुएंगे। क्योंकि, यह ट्रैफिक के लिहाज से एक अहम इलाका है। मुख्य सड़क से दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। हम दुकानदारों के लिए एक जैसे डिजाइन वाले स्टॉल बनाएंगे। हम इस जगह का कायाकल्प करेंगे।

किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर तय होगी जवाबदेही, करेंगे कड़ी कार्रवाई: सीएम योगी

विश्व केसरी ■

गोरखपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि महानगर में किसी भी दशा में जलभराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नाले, नालियों की बड़े पैमाने पर सफाई कराने और बारिश होने पर अधिकाधिक पंपों का संचालन सुनिश्चित करते हुए ध्यान रखा जाए कि कहीं भी जलभराव न होने पाए। जलभराव की समस्या के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सीएम योगी बुधवार को एनेक्सी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जलनिकासी की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उनका सर्वाधिक जोर जलनिकासी को लेकर रहा। उन्होंने दो टूक कहा, 'जो भी जरूरी तैयारी या व्यवस्थाएं करनी हैं, उन्हें सुनिश्चित किया जाए। कहीं भी और किसी भी दशा में जलभराव नहीं दिखना चाहिए।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नाले, नालियों की नियमित सफाई कराकर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इससे नाले चोक न होने पाएं। मुख्यमंत्री ने समझाया कि हमें मौसम के प्रभाव के अनुसार खुद को तैयार रखना होगा। उन्होंने कहा कि नाला निर्माण और मरम्मत के प्रस्ताव समय से लेकर समयबद्ध तरीके से काम पूरा किया जाए। सभी अधिकारी, कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें और कहीं भी नकारात्मक वातावरण न बनने दें।

उन्होंने महानगर के राप्ती कॉम्प्लेक्स, गोरक्ष एंक्लेव, विजय चौराहा तथा धर्मशाला आदि पर हुए जलभराव की जानकारी ली और कहा कि नालों की नियमित रूप से सफाई के बाद उन्हें ढका जाए। नगर निगम के सभी पंप पूरी क्षमता से संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं के साथ ही लोगों को प्रेरित किया जाए कि वह कूड़ा नालियों में न डालें।

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भोगापुरम एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए दिया न्योता

विश्व केसरी ■

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया।

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और टीडीपी संसदीय दल के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायलु के साथ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।

चंद्रबाबू नायडू ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, 'आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मुझे उन्हें आंध्र प्रदेश के भोगापुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करने का अवसर मिला।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर बने इस हवाई अड्डे के जरिए उनके साहस, त्याग और देशभक्ति को सम्मान दिया गया है।

टीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और सुधारों पर आधारित नेतृत्व में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है।

चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी का हवाई यात्रा को आसान और सस्ता बनाने का विजन लाखों लोगों का हवाई सफर करने का सपना पूरा कर रहा है। भोगापुरम हवाई अड्डे के शुरू होने से उत्तर आंध्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इससे कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उनके नेतृत्व में भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश भी 'स्वर्ण आंध्र प्रदेश' बनाकर इस अभियान में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।'

मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी कि भोगापुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन एक अगस्त को होगा।

यात्री टर्मिनल भवन के उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री जीएमआर स्किल डेवलपमेंट सेंटर, एविएशन हब-यूनिवर्सिटी और जीएमआर-मानसास एजुकेशन सिटी का भी उद्घाटन करेंगे।

ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 'बहुदा यात्रा' की तैयारियों की समीक्षा की, भीड़ प्रबंधन पर दिया जोर

विश्व केसरी ■

भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बुधवार को अधिकारियों को आगामी 'बहुदा यात्रा' के दौरान प्रभावी भीड़ प्रबंधन और सुचारू सूचना प्रवाह पर जोर देने का निर्देश दिया। बहुदा यात्रा भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और अन्य देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर की वापसी यात्रा है, जो 24 जुलाई को पुरी में आयोजित होने वाली है।

बहुदा यात्रा वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु विश्व-प्रसिद्ध पुरी उत्सव के नौवें दिन गुंडिचा मंदिर से 12वीं शताब्दी के मंदिर तक भाई-बहन देवताओं के रथों को खींचते हैं।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में बहुदा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री मांझी ने श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों से पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने की भी अपील की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि वार्षिक रथ यात्रा उत्सव से संबंधित सभी अनुष्ठान अब तक सुचारू रूप से संपन्न हुए हैं। लगातार बारिश, प्रतिकूल मौसम, गर्मी और उमस के बावजूद, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और श्रद्धालुओं का समर्पण और प्रतिबद्धता अप्रभावित रही।

माझी ने सेवकों की निष्ठा और समर्पण की सराहना की और उनकी अमूल्य सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने उत्सव के प्रबंधन में लगे सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित टीम प्रयास की भी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री को बताया गया कि जिला प्रशासन और पुलिस पुरी में निरंतर निगरानी रख रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं की नियमित रूप से निगरानी कर रहे हैं।

पटना में राजभवन मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, वॉटर कैनन और आंसू गैस छोड़े

विश्व केसरी ■

पटना। पटना में नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को राजभवन की ओर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस और हजारों छात्रों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ।

सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाकर जेपी गोलंबर पर मार्च को रोक दिया, जिससे शहर में घंटों तक तनाव बना रहा। इस दौरान, छात्रों से शांतिपूर्वक वापस लौटने को कहा गया।

जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने शुरू में वॉटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े। जब भीड़ आगे बढ़ती रही तो प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया।

पुलिस की कार्रवाई के बावजूद हजारों छात्र विरोध स्थल पर डटे रहे और नारे लगाते रहे।

लगभग 20 मिनट की झड़प के बाद, प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर पर बैरिकेड्स तोड़ने में कामयाब रहे और डाकबंगला क्रॉसिंग की ओर बढ़ गए।

इसके बाद पुलिस ने डाकबंगला क्रॉसिंग पर एक और सुरक्षा घेरा बनाया, जहां अनुमानित 7,000 छात्र जमा हो गए।

अतिरिक्त बल तैनात किए जाने के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा स्थिति का जायजा लेते देखे गए।

इस हंगामे के दौरान पुलिस के एक इंस्पेक्टर जनरल की एस्कॉर्ट गाड़ी पर कथित तौर पर हमला किया गया और उसे नुकसान पहुंचाया गया।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि भाजपा का झंडा लगी कुछ गाड़ियों को निशाना बनाया गया।

खबरों के अनुसार, डाकबंगला क्रॉसिंग से गुजर रहे एक भाजपा विधायक को प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करने के बाद वह जगह छोड़ना पड़ा।

भाजपा-कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सियासी गलियारों में बढ़ी हलचल

लोकतंत्र का अपमान कांग्रेस की यही पहचान!
संविधान विरोधी कांग्रेस शर्म करो
राहुल गांधी की देश जलाने की कोशिश नहीं चलेगी
कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ
समाधान नहीं, टकराव - कांग्रेस का यही स्वभाव!
भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

विश्व केसरी

रायपुर। दिल्ली में राहुल गांधी के पीएम आवास घेराव के विरोध में छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस नेता आमने-सामने हो गए हैं। भाजपा नेता कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने निकले। इस दौरान राजीव भवन के पास कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए, जिससे दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और दो बार आंसू गैस छोड़ी गई। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी देश में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मामले के लिए भाजपा जिम्मेदार है। संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की गई। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं पर नहीं, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस छोड़ी गई।

आंसू गैस के असर से मची अफरा-तफरी

प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और 5 बार आंसू गैस के गोले छोड़े। आंसू गैस के असर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कई कार्यकर्ता व पुलिस जवान इसकी चपेट में आ गए।

आंसू गैस से पुलिसकर्मी, रिपोर्टर भी प्रभावित

प्रदर्शन के दौरान छोड़ी गई आंसू गैस के असर से पुलिस जवानों के साथ कवरेज करने पहुंचे रिपोर्टर भी प्रभावित हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आंसू गैस भाजपा कार्यकर्ताओं पर नहीं, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर छोड़ी गई। वहीं, पार्टी ने महिला कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी का आरोप लगाते हुए पुलिस पर पक्षपात करने का भी दावा किया।

घेराव के दौरान लगा लंबा जाम

भाजपा के घेराव प्रदर्शन के चलते शंकर नगर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहा। बैरिकेडिंग और प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी के कारण सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने प्रदर्शन खत्म होने के बाद बैरिकेडिंग हटाकर यातायात सामान्य की गई।

VARUN
VARUN

शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अंबेडकर चौक के पास केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने किया। इस दौरान भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अंबेडकर चौक पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले भाजपा सरकार का एक पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने का प्रयास किया, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को चकमा देते हुए दूसरा पुतला भी जलाकर भाजपा सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों छात्र छात्राएं नीट पेपर लीक मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर लोकतंत्र को शर्मसार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में अनेक छात्रों को गंभीर चोटें आईं, कई छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ तथा प्रदर्शन में शामिल नहीं रहे आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, तब पुलिस ने उनके साथ भी जबरदस्ती करते हुए उन्हें घसीटकर हिरासत में लिया। यह घटना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि देशभर में बढ़ते जनआक्रोश और छात्रों के व्यापक आंदोलन के दबाव में अंततः प्रधानमंत्री को भी नीट पेपर लीक मामले पर अपना बयान जारी करना पड़ा। कांग्रेस छात्रों के अधिकारों और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी तथा भाजपा सरकार की जनविरोधी और दमनकारी नीतियों का हर स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी। इस कार्यक्रम मे कुलदीप जुनेजा प्रमोद दुबे पंकज शर्मा आकाश शर्मा सुबोध हरितवाल कन्हैया अग्रवाल उधो वर्मा दिनेश ठाकुर मनोज कंदोई सुशांत डे प्रशांत ढेंगडी आकाश तिवारी मनोज बंजारे राज देवांगन दीपक चौबे सुरेश धीवर ओम श्रीवास सुधा हिरेंद्र देवांगन सरोज मिलिंद गौतम सुजीत सिंह कमल धृतलहरे किशनलाल बाजारी शब्बीर खान रूबल मेहता सुधीर बंजारे प्रीति सोनी उपस्थित थे।

संक्षिप्त खबरें

विश्व केसरी

रायपुर। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट नई दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पांडे ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर के वरिष्ठ पत्रकार अमित मिश्रा को नेशनल कौंसिलर मनोनीत किया है। अमित मिश्रा पिछले 45 वर्षों से अनवरत पत्रकारिता के क्षेत्र में है। वे लम्बे समय से प्रदेश के विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं। उनकी नियुक्ति आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय सचिव श्री शिव शंकर सोन पिपरे ने अनुशंसा राष्ट्रीय महासचिव को भेजी थी।

विनीता शर्मा को मिली पीएच.डी. की उपाधि

विश्व केसरी

रायपुर। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने विनीता शर्मा को हिन्दी विषय में 'गिरीश पंकज के कथा साहित्य में यथार्थबोध 'विषय पर शोधकार्य पूर्ण करने के उपरांत पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की है। उन्होंने अपना शोधकार्य शोध निर्देशक डॉ. राजेश दुबे, पूर्व प्राचार्य, शहीद राजीव पांडे शासकीय महाविद्यालय, भाटागांव (रायपुर) के निर्देशन तथा सह-शोध निर्देशक डॉ. सविता मिश्रा, पूर्व प्राचार्य, शासकीय राजीव लोचन स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजिम जिला- गरियाबंदके सह-निर्देशन में शासकीय दूधाधारी बजरंग महाविद्यालय, रायपुर स्थित शोध केंद्र में पूर्ण किया। विनीता शर्मा की इस उपलब्धि पर उनके गुरुजनों, परिजनों, मित्रों एवं शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी हैं।

युवाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं स्ट्रोक के मामले

विश्व केसरी

रायपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तंत्रिका संबंधी रोग अब पूरी दुनिया में दिव्यांगता का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। विश्व की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी, यानी 3.4 अरब से ज्यादा लोग मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी किसी न किसी बीमारी से प्रभावित हैं। हर वर्ष इन बीमारियों के कारण 1.1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। यही वजह है कि तंत्रिका संबंधी रोग आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल हो चुके हैं। इन बीमारियों में स्ट्रोक सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। भारत में हर वर्ष लगभग 12.5 लाख नए स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, पिछले तीन दशकों में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तंबाकू का सेवन, मानसिक तनाव, अपर्याप्त नींद, अस्वस्थ जीवनशैली और बढ़ती आयु इसके प्रमुख कारण हैं। इसके साथ ही मधुमेह और उच्च रक्तचाप की दवाओं का अनियमित सेवन तथा नियमित चिकित्सकीय जांच और फॉलो-अप की कमी इस जोखिम को और अधिक बढ़ा रही है।

एफएसएसएल की 'निरंतर वैधता' व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग

विश्व केसरी

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जैन, वाइस चेयरमेन सुरिन्दर सिंह, जीवत बजाज, प्रदेश महामंत्री अवनीत सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय पटेल, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, वासु माखीजा, श्री राम मंधान, भरत जैन, राकेश ओचवानी एवं शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य अमर पारवानी के नेतृत्व में कैट छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने आज छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्याम बिहारी जायसवाल से सौजन्य भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारत सरकार के भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 10 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुरूप खाद्य व्यवसाय लाइसेंस एवं पंजीयन की 'निरंतर वैधता' व्यवस्था को छत्तीसगढ़ में भी शीघ्र लागू करने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर अमर पारवानी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था Ease of Doing business को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके लागू होने से खाद्य व्यवसाय संचालकों को बार-बार लाइसेंस एवं पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिलेगी, अनावश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएँ कम होंगी।

छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में 6,967 मौतें, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, 10 दिन में मांगा जवाब

विश्व केसरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बेकाबू होते सड़क हादसों और लगातार गंवाती जिंदगियों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य में एक साल के भीतर 6 हजार 967 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौत पर गंभीर चिंता जताई है। बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट परिसर में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित प्रशासनिक विभागों को शपथ पत्र के साथ 10 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट में कोर्ट कमिश्नर द्वारा पेश किए गए

आधिकारिक आंकड़े प्रदेश की सड़कों की भयावह तस्वीर बयां करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान राज्य भर में कुल 15 हजार 484 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 6 हजार 967 बेकसूर लोगों की जान चली गई और 13 हजार 156 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। चिंता की बात यह है कि साल 2026 की शुरुआत से लेकर 31 मई तक के शुरुआती पांच महीनों में ही 6 हजार 891 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 3 हजार 170 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि यदि तत्काल कड़े कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी विकराल रूप ले सकती है।

अदालत की इस सख्ती के पीछे जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की भारी अनदेखी मुख्य वजह बनकर सामने आई है। नियमों के अनुसार हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। कोर्ट कमिश्नर ने बेंच को बताया कि सरगुजा जिले में साल 2025 के दौरान सड़क हादसों में 300 से अधिक मौतें हुईं, फिर भी पूरे साल में महज एक बैठक आयोजित की गई। कांकेर जिले का हाल भी ऐसा ही रहा, जहां सालभर में सिर्फ एक बार समिति की औपचारिक बैठक बुलाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि जमीनी स्तर पर हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही है।

चीफ जस्टिस ने क्या कहा ?

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने हाईवे पर बैठे आवारा मवेशियों और सरेराह खड़ी भारी गाड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। अदालत ने पाया कि औद्योगिक क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 10 टन की क्षमता वाले वाहनों में 22 से 25 टन तक माल लादा जा रहा है और वजन जांचने वाली वेइंग मशीनें लंबे समय से बंद पड़ी हैं।

बारिश के बीच नगर पालिका अध्यक्ष ने शहर का लिया जायजा

विश्व केसरी

महासमुंद (अनिल चौधरी)। रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच शहर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाए रखने की दिशा में नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नालियों, नालों और मुख्य सड़कों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर जमीनी स्थिति की जानकारी ली। बारिश के चलते कुछ स्थानों पर पानी जमा होने और नालियों में कीचड़ की समस्या सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और सफाई अमले को तत्काल आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

साहू ने कहा कि मानसून के दौरान शहर में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर रखना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर की प्रमुख नालियों और बड़े नालों की नियमित रूप से सफाई कराई जा रही है, ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल सके और लोगों को जलभराव जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सफाई

KOMATSU
GD 535

व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी वार्डों में स्वच्छता कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष ने नागरिकों से भी शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ महासमुंद के निर्माण में आम जनता की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों को चाहिए कि वे कूड़ा-कचरा नालियों, सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर न डालें। घरों से निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में एकत्र कर नगर पालिका की डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था के माध्यम से स्वच्छता दीदियों को सौंपें।

अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगा 10 प्रतिशत का आरक्षण

विश्व केसरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के युवाओं और किसानों के हित में दो बड़े नीतिगत निर्णयों पर अंतिम मुहर लगाई गई। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की शासकीय सेवाओं में सम्मानजनक अवसर देने के उद्देश्य से सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक प्रावधान लागू किया है। इसके साथ ही खरीफ और रबी सीजन के दौरान प्रदेश भर के किसानों को रासायनिक उर्वरकों की सुचारू व समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसलें

मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदेश के किसानों को खरीफ एवं रबी मौसम में उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरक आपूर्ति, वितरण एवं प्रबंधन से संबंधित विषयों पर सुझाव, अनुशंसा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

उप समिति में किन्हें किया गया शामिल ?

इस उप समिति में उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अध्यक्ष तथा कैबिनेट मंत्री, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग एवं कैबिनेट मंत्री, वित्त विभाग को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। उप समिति आवश्यकतानुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी तथा उर्वरकों की उपलब्धता एवं आपूर्ति से संबंधित विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी।

बांगो बांध का जलस्तर बढ़ा, गेट खोलने की तैयारी, बाढ़ प्रभावित गांवों में मुनादी

विश्व केसरी

कोरबा (बबलू श्रीवास)। कोरबा में लगातार हो रही बारिश के बीच मिनीमाता बांगो बांध प्रशासन ने वर्षाकाल 2026 को लेकर अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग ने बताया कि बांगो जलाशय का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में जलभराव 354.61 मीटर यानी 71.67% तक पहुंच चुका है।

जलस्तर पर लगातार निगरानी

विभाग के अनुसार फिलहाल जलाशय से विद्युत संयंत्रों को पानी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर गेट खोलने का निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि 1 जून से 21

जुलाई तक कोरबा जिले में 409.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एसके भारती ने बताया कि हसदेव नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों, खनिज खदानों, औद्योगिक इकाइयों, ठेकेदारों और अन्य संस्थानों को अपनी चल-अचल संपत्तियां सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अचानक आई बाढ़ से होने वाली क्षति के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं

प्रभावित गांवों में मुनादी के निर्देश

संभावित बाढ़ को देखते हुए बांगो, चर्रा, पोड़ी उपरोड़ा, कोनकोना, लेपरा, टुनियाकछार, पाथा, गाड़ाघाट, छिनमेर, कछार, कलमीपारा, जूनापारा, तिलाईडांड, डुगुपारा, टुंगुमांड़ा, छिर्रापारा, मछलीबाटा, कोरियाघाट, धनगांव, डोंगाघाट, नरमदा, औराकछार, सोनगुड़ा, जेलगांव, झाबू, नवागांव, तिलसाभाटा, लोतलोता, स्याहीमुड़ी, कोडा, हथमार, झोरा और सिरकीकला सहित अन्य गांवों में चेतावनी की मुनादी कराने के निर्देश दिए गए।

आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कई सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हुए शामिल

विश्व केसरी

रायपुर। आम आदमी पार्टी की जनहितकारी नीतियों, सामाजिक न्याय की विचारधारा एवं संगठन के निरंतर विस्तार से प्रभावित होकर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से जुड़े अनेक प्रमुख कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी, दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक मुकेश अहलावत ने सभी नवप्रवेशी साथियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के एस.सी. विंग के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद जांगड़े के नेतृत्व एवं सहयोग से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष (एस.सी. विंग) उदय चरण बंजारे, भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारी भागवत टंडन, शंकर बंजारे, शांतनु जांगड़े एवं विकास पाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए पार्टी की विचारधारा एवं जनहितकारी नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया। नवप्रवेशी साथियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पारदर्शी शासन और ईमानदार राजनीति के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है।

संपादकीय

ये अम्बेडकरवाद की आंधी हैं

डॉ.संजीव कुमार

एक व्यंग के रूप में उपजी सोशल मीडिया द्वारा स्थापित कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आज देश में सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंका है सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी. इस सोशल मीडिया द्वारा उठाए गए सवाल और तूफान ने हमारे सामने तीन सवाल खड़े किए हैं. पहला जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग कब तक अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे ? दूसरा सत्ता में बैठे हुए लोग शिक्षा से कब तक मजाक करेंगे? और आखिरी,शिक्षित युवाओं के लिए सरकार कब संवेदनशील रहेगी?

वर्तमान में जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा आंदोलन खड़ा किया गया है उसकी बुनियाद 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त जी द्वारा दिए गये उस विवादित बयान से हुआ है जिसमे उन्होंने कहा था 'कुछ युवा कॉकरोच (तिलचट्टों) की तरह हैं, जिन्हें अपने पेशे में कोई जगह या रोजगार नहीं मिलता. इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई (RTI) एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।' इसके साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को समाज का 'परजीवी' (Parasites) भी कहा था. उनके इस बयान से देश भर के युवा आक्रोशित हो उठे. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयान का कड़ा विरोध किया . दूसरी तरफ अमेरिका में बैठे अभिजीत दीपके ने व्यंग के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया. देखते ही देखते देश भर में हफ्ते भर के अंदर इसके भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा लोग फॉलोअर हो गए.

डॉ. बाबासाहेब बी. आर. आंबेडकर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिति
पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह!
छात्रों पर चली एक-एक लाठी का जवाब देना होगा!

12 मई को नीट की परीक्षा खुद एनडीए द्वारा रद्द करने की घोषणा के बाद कुछ ही हफ्तों में देश भर से लगभग 12 विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं. इस घटना को कॉकरोच जनता पार्टी अपना मुद्दा बनती है और फिर अभिजीत दीपके अपने दो सहयोगियों सौरव दास एवं अनुराग रांका के साथ मिलकर 20 जून से जंतर मंतर पर आंदोलन की घोषणा करते हैं. एक हफ्ते तक इनका आंदोलन देशभर में यह संदेश पहुंचाने में कामयाब होता है कि वर्तमान सरकार किस तरह से शिक्षा तथा रोजगार पर अपनी जवाब देही नहीं तय कर पा रही है. पूरा देश देख रहा है कि वर्तमान सरकार शिक्षा के मायने में हर स्तर पर लगातार असफल हो रही है. ऐसी स्थिति में भी अगर कुछ युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन-रात कड़ी परिश्रम करते हैं और जब कोई परीक्षा रद्द हो जाती है अथवा लीक हो जाती है तो इन 18 -19 साल के युवाओं की मनोदसा टूट जाती हैं.

अभी जंतर मंतर पर जो गुस्सा दिखाई दे रहा है युवाओं का, दरअसल वह गुस्सा सिर्फ एक परीक्षा लिक को लेकर ही नहीं है, यह गुस्सा सरकार द्वारा लगातार भारतीय शिक्षा की स्थिति को खराब करने, नियुक्तियों में लगातार कमी, परीक्षा का समय पर नहीं होना, परीक्षाओं का टाल- मटोल करना, सरकार को खुद को कानून से ऊपर समझना, बुलडोजर से न्याय करना, दलितों पर देश में बढ़ते हमले, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार, प्रधानमंत्री का देश और दुनिया में देश की किरकरी करवाना, 12 साल में प्रधानमंत्री द्वारा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाना, और वर्तमान में अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी इत्यादि कई मामले शामिल है जो अब ज्वाला बन चुकी है . सरकार को लग रहा था कि यह आंदोलन सोशल मीडिया द्वारा एक मामूली प्रदर्शन हैं, इसलिए वह लगातार इसकी उपेक्षा कर रही थी. 28 जून को जब प्रख्यात वैज्ञानिक एवं समाजसेवी सोनम वांगचुक जी इस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं तब इसकी गूंज देश के बाहर पहुंचने लगती है. न्यूयार्क लंदन और नीदरलैंड के शहरों से सोनम वांगचुक तथा कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में वहां भी धरने होने लगते हैं. 16 जुलाई को कुछ पुलिसों द्वारा अभिजीत दीपके के साथ बदतमीजी की जाती है जिसके लिए अभिजीत प्रशासन कर्मियों से रियायत की मांग करते हैं. 17 जुलाई को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर सोनम वांगचुक से मुलाकात करने जंतर मंतर पहुंचते हैं. वहां आंदोलन में बैठे छात्राओं तथा सोनम वांगचुक की हालत देखकर वें द्रवित हो उठते है और सोनम वांगचुक तथा अभीजित के सहयोगियों से पूछते है की आपके आन्दोलन को मजबूत करने के लिए कितने लोग चाहिए ? आप 20 जुलाई को संसद मार्च कीजिए .अत: अभीजित के सभी सहयोगी 20 जुलाई को शांतिपूर्ण संसद मार्च की घोषणा करते इससे पहले 18 जुलाई को सुबह 4 बजे बर्बरता से वांगचुक जी को सादे कपडे में दिल्ली पुलिस के लोग उठा ले जाते है ।

छात्र आंदोलन: मुद्दों से भटकती बहस और भविष्य की चिंता

डॉ. सत्यवान सौरभ

लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन केवल अधिकार नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम भी है। जब व्यवस्था में कोई गंभीर खामी सामने आती है, तब जनता अपनी आवाज़ बुलंद करती है और सरकार से जवाब मांगती है। विशेष रूप से जब मामला लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हो, तब विरोध का स्वर और अधिक स्वाभाविक हो जाता है। NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरों ने पूरे देश के युवाओं और उनके अभिभावकों को चिंतित किया। वर्षों की कठिन मेहनत के बाद यदि किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग जाए, तो आक्रोश पैदा होना असामान्य नहीं है। किंतु इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा प्रश्न भी खड़ा किया कि क्या छात्र आंदोलनों का उद्देश्य वास्तव में छात्रों का भविष्य रह गया है, या फिर वे धीरे-धीरे राजनीतिक और वैचारिक संघर्षों का मंच बनते जा रहे हैं?

किसी भी छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नैतिकता होती है। जब छात्र अपने अधिकारों और भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं, तब समाज उनके साथ खड़ा होता है। अभिभावक, शिक्षक और आम नागरिक भी उनकी मांगों को उचित मानते हैं। लेकिन जैसे ही आंदोलन का केंद्र बदलने लगता है और मूल मुद्दे से असंबंधित विषय मंच पर आने लगते हैं, तब उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यदि परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध का मंच ऐसे नारों, भाषणों या विवादों का केंद्र बन जाए जिनका शिक्षा व्यवस्था से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो आंदोलन की गंभीरता कम होती है और वास्तविक मुद्दा पीछे छूट जाता है।

आज देश का युवा पेपर लीक से परेशान है। उसे इस बात की चिंता है कि वर्षों की मेहनत कहीं किसी अपराधी गिरोह की वजह से व्यर्थ न चली जाए। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह होना चाहिए कि पेपर लीक कैसे रुकेंगे, परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित कैसे बनाया जाएगा, दोषियों को कितनी जल्दी और कितनी कठोर सजा मिलेगी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-से संस्थागत सुधार किए जाएंगे। यदि इन मूल प्रश्नों के स्थान पर केवल राजनीतिक नारे और सरकार विरोध या सरकार समर्थन की बहस प्रमुख हो जाए, तो समाधान की दिशा कमजोर पड़ जाती है।

यह भी स्वीकार करना होगा कि पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है। अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग सरकारों के समय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के मामले सामने आते रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि समस्या किसी एक दल, एक मंत्री या एक सरकार तक सीमित नहीं है। समस्या उस तंत्र में है जिसमें अपराधी गिरोह सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं। इसलिए यदि हर बार केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही चर्चा सीमित रहेगी, तो वास्तविक अपराधी बच निकलेंगे और विद्यार्थी बार-बार पीड़ित होंगे।

किसी मंत्री का इस्तीफा लोकतांत्रिक जवाबदेही का विषय हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है। मंत्री बदलने से व्यवस्था तभी बदलेगी जब प्रशासनिक सुधार, तकनीकी सुरक्षा, पारदर्शी जांच और कठोर दंड व्यवस्था लागू होगी। यदि जड़ पर प्रहार नहीं होगा तो केवल चेहरे बदलने से परिणाम नहीं बदलेंगे। इसलिए छात्र आंदोलनों का केंद्र व्यक्ति नहीं, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।

सोशल मीडिया के दौर में आंदोलनों की दिशा बहुत तेजी से बदलती है। कुछ सेकंड की वीडियो क्लिप, एक नारा या एक पोस्ट पूरे आंदोलन की छवि तय कर देती है। यही कारण है कि आंदोलन से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। यदि मंच पर ऐसे नारे सुनाई दें जिनका परीक्षा या शिक्षा से कोई संबंध न हो, तो आम नागरिक यह सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या आंदोलन का मूल उद्देश्य वही है जो शुरुआत में बताया गया था। लोकतंत्र में विचारधाराओं का स्थान है, लेकिन जब छात्र आंदोलन वैचारिक प्रतिस्पर्धा का माध्यम बन जाए, तब सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है जिनके नाम पर आंदोलन शुरू हुआ था।

सार्वजनिक जीवन में सक्रिय किसी भी व्यक्ति—चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो, छात्र नेता हो या आंदोलन का चेहरा—उसकी बातों से सहमति और असहमति दोनों हो सकती हैं। लोकतंत्र इसी विविधता का नाम है। लेकिन किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन व्यक्तियों की लोकप्रियता से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और परिणामों से होना चाहिए। यदि आंदोलन छात्रों के भविष्य के लिए शुरू हुआ है, तो उसकी हर गतिविधि, हर नारा और हर मांग उसी उद्देश्य को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। अन्यथा समाज का विश्वास कमजोर पड़ने लगता है।

आज आवश्यकता केवल दोषारोपण की नहीं, बल्कि व्यापक सुधार की है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए अत्याधुनिक डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था विकसित करनी होगी। प्रश्नपत्रों के निर्माण से लेकर वितरण तक हर चरण में जवाबदेही तय करनी होगी। साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा। पेपर लीक में शामिल संगठित गिरोहों की संपत्ति जब्त करने, त्वरित न्याय और आजीवन प्रतिबंध जैसे कठोर उपायों पर गंभीरता से विचार करना होगा। जब तक अपराधियों को यह भय नहीं होगा कि उनके अपराध की कीमत बहुत भारी होगी, तब तक समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।

राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। सत्ता पक्ष को आलोचना से बचने के बजाय पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि विपक्ष को केवल सरकार की आलोचना तक सीमित रहने के बजाय रचनात्मक सुझाव भी देने चाहिए। यदि हर समस्या केवल राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखी जाएगी, तो छात्रों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं से कम होता जाएगा। शिक्षा और युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण विषय है।

समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। कई बार हम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, अधूरी सूचनाओं या भावनात्मक संदेशों के आधार पर तुरंत पक्ष-विपक्ष तय कर लेते हैं। जबकि किसी भी आंदोलन या विवाद का मूल्यांकन तथ्यों, प्रमाणों और संतुलित दृष्टिकोण से होना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, लेकिन असहमति तभी सार्थक होती है जब वह विवेक और जिम्मेदारी के साथ व्यक्त की जाए।

छात्रों को भी यह समझना होगा कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी नैतिक विश्वसनीयता है। यदि वे अपने मुद्दों पर एकजुट रहेंगे, तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन यदि उनका आंदोलन राजनीतिक ध्रुवीकरण का माध्यम बन जाएगा, तो उनकी वास्तविक मांगें पीछे छूट जाएँगी। इतिहास गवाह है कि सफल जनांदोलन वही रहे हैं जिन्होंने अपने मूल उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा।

भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। यह जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। यदि युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं से डगमगाने लगे, तो उसका प्रभाव केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए पेपर लीक जैसी घटनाओं को केवल समाचार या राजनीतिक विवाद मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, न्यायपालिका, जांच एजेंसियाँ, शैक्षणिक संस्थान, अभिभावक, शिक्षक और छात्र—सभी मिलकर ऐसी व्यवस्था तैयार करें जिसमें मेहनत का सम्मान हो, प्रतिभा को अवसर मिले और किसी भी छात्र को यह भय न रहे कि उसकी सफलता किसी अपराधी गिरोह की वजह से छिन सकती है।

लोकतंत्र में आंदोलन आवश्यक हैं, लेकिन आंदोलन तभी प्रभावी होते हैं जब वे अपने मूल उद्देश्य से न भटकें। यदि लक्ष्य छात्रों का भविष्य है, तो बहस भी उसी पर केंद्रित रहनी चाहिए। व्यक्ति आएँगे-जाएँगे, सरकारें बदलेंगी, राजनीतिक दल सत्ता में आएँगे और जाएंगे, लेकिन भारत का भविष्य आज का विद्यार्थी ही तय करेगा। इसलिए छात्र आंदोलनों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि शिक्षा सुधार और पारदर्शी व्यवस्था का माध्यम बनाना ही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

जंतर-मंतर की गूँज : दिनकर और नागार्जुन की लोकतांत्रिक चेतना का समकालीन पाठ

गोलेंद्र पटेल

दिल्ली का जंतर-मंतर केवल एक भौगोलिक स्थल नहीं है; वह भारतीय लोकतंत्र का ऐसा सार्वजनिक मंच है जहाँ समय-समय पर नागरिक अपनी आकांक्षाएँ, असहमति और अधिकारों की आवाज़ दर्ज करते रहे हैं। आज जब विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, रोजगार, संस्थागत विश्वसनीयता और अपने भविष्य से जुड़े प्रश्नों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, तब यह आंदोलन किसी एक प्रशासनिक निर्णय के विरोध तक सीमित नहीं रह जाता। यह लोकतंत्र के उस मूल प्रश्न को सामने लाता है कि क्या सत्ता नागरिकों की आवाज़ को सुनने के लिए पर्याप्त संवेदनशील और उत्तरदायी है? ऐसे समय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' और जनकवि नागार्जुन का काव्य असाधारण प्रासंगिकता के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है। दोनों कवि भिन्न स्वरों के रचनाकार हैं। दिनकर का स्वर ओज, राष्ट्रीय चेतना और नैतिक उद्बोधन का है, जबकि नागार्जुन का स्वर जनपक्षधर प्रतिरोध, तीखे व्यंग्य और सत्ता की निर्भीक आलोचना का। किंतु दोनों की काव्य-दृष्टि एक ही लोकतांत्रिक सत्य पर जाकर मिलती है। सत्ता जनता के लिए है, जनता सत्ता के लिए नहीं। दिनकर की कविता 'दिल्ली' सत्ता के वैभव और जनता की पीड़ा के बीच उपस्थित गहरी विडम्बना को उद्घाटित करती है। राजधानी यहाँ केवल एक नगर नहीं, बल्कि उस शासन-व्यवस्था का प्रतीक बन जाती है जो कभी-कभी नागरिकों की वेदना से दूर होती चली जाती है। कवि का प्रश्न आज भी उतना ही तीखा है। जब समाज का बड़ा वर्ग संकट, असुरक्षा और निराशा से गुजर रहा हो, तब उत्सव और वैभव का नैतिक औचित्य क्या है? 'कूक रही क्यों नियति व्यंग्य से इस गोधूलि-लगन में?/ मरघट में तू साज रही दिल्ली! कैसे शृंगार?/ यह बहार का स्वांग अरी, इस उजड़े हुए चमन में!' जैसी पंक्तियाँ वस्तुत: सत्ता से आत्मावलोकन की माँग करती हैं। दिनकर स्पष्ट संकेत देते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक शासन की प्रतिष्ठा भवनों, समारोहों और शक्ति-प्रदर्शन से नहीं, बल्कि जनता के दु:ख के प्रति उसकी संवेदनशीलता से निर्मित होती है। इसी कविता में किसान, मज़दूर और वंचित वर्गों की पीड़ा को स्वर देते हुए दिनकर बताते हैं कि उपेक्षित नागरिकों की कराह अंतत: राष्ट्र की कराह बन जाती है। आज के संदर्भ में यही संवेदना उन विद्यार्थियों और युवाओं तक भी विस्तृत दिखाई देती है जो अपनी मेहनत, प्रतिभा और भविष्य की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसे प्रश्न व्यवस्था-विरोध नहीं, बल्कि व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण और उत्तरदायी बनाने की स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। यदि 'दिल्ली' सत्ता से संवेदना की अपेक्षा करती है, तो 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' लोकतंत्र में जनता की सर्वोच्चता का उद्घोष करती है। दिनकर का प्रसिद्ध आह्वान 'सदियों की ठण्डी-बुझी राख सुगबुगा उठी,/मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है;/ दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो,/ सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।' किसी हिंसक सत्ता-परिवर्तन का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का स्मरण है।

बोधकथा

संवेदनशीलता और सही दिशा

एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। वह बड़ा ही समझदार और परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थीं जो हमेशा उसकी हार का कारण बनती थीं। अर्जुन का सपना था कि वह अमीर बनें, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ कामयाबी की राह में रुकावटें आती रहीं। एक दिन, अर्जुन अपने दोस्त सुरेश के साथ गांव के पंचायत भवन में गया। वहां उन्होंने सुना कि एक महान योगी गांव के पास आ रहे हैं और वह सभी जीवों के कर्मों को जान सकते हैं। अर्जुन ने दोस्त सुरेश के साथ तय किया कि वे इस योगी के पास जाकर अपने कर्मों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। योगी के पास पहुँचकर, अर्जुन और सुरेश ने उनकी आज्ञाओं का पालन किया और उनके सामने बैठे। योगी ने दोनों के कर्मों को जानने का प्रयास किया और बताया कि उनके कर्मों के बल पर ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अर्जुन ने सबसे पहले योगी को अपने कई सारे परिश्रमों के बारे में बताया। उसने कहा कि वह हमेशा परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी उसका सपना पूरा नहीं हो पाता। योगी ने उसके कर्मों को देखकर बताया कि उसने तो परिश्रम किया, लेकिन उसके कर्मों में संवेदनशीलता और सही दिशा नहीं दी। उसने कहा कि अगर वह अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता तो उसका सपना पूरा हो सकता था। अर्जुन ने इसे सबसे गहराई से समझने की कोशिश की, और योगी के संदेश को समझकर उसने अपने कर्मों में सुधार करने का निर्णय लिया। उसने योगी से सीखा कि कर्मों को न केवल बिना उम्मीद के किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सही दिशा में करने की भी आवश्यकता होती है। अर्जुन ने योगी की सीखों का पालन किया और अपने कर्मों में संवेदनशीलता और सही दिशा देने लगा। उसके कर्मों में सुधार होता गया और वह अपने सपने की ओर बढ़ता गया। कुछ महीनो बाद अर्जुन का सपना पूरा हो गया ।

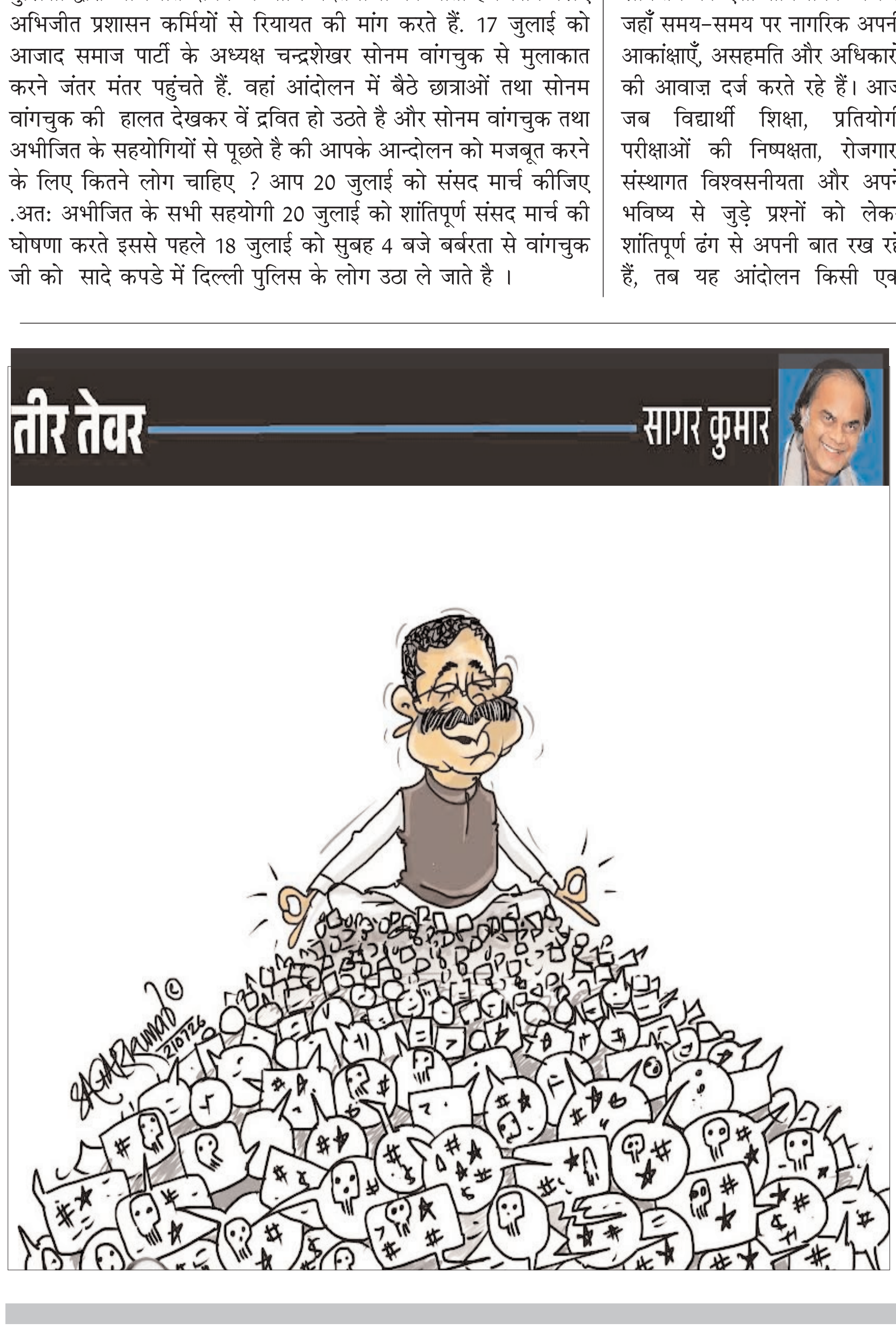

व्यंग्य केसरी

भगवान भी फ़ाइलों में!

अशोक मतवाला

कहते हैं भगवान सबके मालिक हैं। लेकिन लगता है अब उन्हें भी अपनी ही संपत्ति देखने के लिए आवेदन-पत्र भरना पड़ेगा। मंदिर में प्रवेश से पहले शायद कोई बाबू पूछ बैठे— 'भगवान से मिलने आए हैं? पहले टोकन लीजिए, फिर खिड़की नंबर तीन पर हस्ताक्षर कराइए।

सुना है सरकार मंदिरों का प्रबंधन बेहतर करना चाहती है। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए होंगे— 'वत्स! पहले धरती का प्रबंधन तो ठीक कर लो, फिर मेरी चिंता करना।

अब कल्पना कीजिए कि मंदिर भी सरकारी दफ्तर बन जाए। घंटी बजाने के लिए परमिट, आरती के लिए ऑनलाइन स्लॉट, प्रसाद लेने के लिए आधार लिंक और दर्शन के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन। यदि नेटवर्क बैठ गया तो भगवान भी 'सर्वर डाउन' की कृपा में लीन हो जाएँ।

दानपात्र के पास एक बोर्ड लगा होगा— 'दान देकर रसीद लेना न भूलें। बिना रसीद का पुण्य अगले वित्तीय वर्ष में समायोजित नहीं किया जाएगा।

भक्त भी कम नहीं हैं। पहले भगवान से संतान, नौकरी और सुख-समृद्धि माँगते थे। अब प्रार्थना बदल जाएगी— 'हे प्रभु! मेरी फ़ाइल बिना आपत्ति के पास करा देना।

भगवान बेचारे सोच रहे होंगे कि पहले लोग सीधे दिल से बात करते थे। अब हर बात नोटशीट पर लिखी जा रही है।

मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं एक दिन भगवान को भी कार्यालय समय का पालन न करना पड़े। सुबह नौ बजे हाज़िरी, शाम पाँच बजे छुट्टी। मंगलवार को निरीक्षण, गुरुवार को ऑडिट और शनिवार को विशेष समीक्षा बैठक। रविवार को अवकाश इसलिए नहीं कि भगवान आराम करेंगे, बल्कि इसलिए कि दफ्तर बंद रहेगा।

अगर यही चलता रहा तो किसी दिन मंदिर के बाहर बोर्ड टंगा मिलेगा— 'भगवान आज प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यस्त हैं। असुविधा के लिए खेद है।

सबसे मज़ेदार दृश्य तब होगा जब नारद मुनि स्वर्ग से आएँगे और उनसे कहा जाएगा, 'पहले विज़िटर पास बनवाइए। बिना अनुमति अंदर जाना नियमों के विरुद्ध है।

आस्था का मूल्य लेखा-जोखा नहीं होता। मंदिर श्रद्धा का स्थान है, जहाँ मन झुकता है, सिर नहीं गिना जाता। व्यवस्था होनी चाहिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि भगवान स्वयं अपनी पहचान साबित करते फिरें।

वरना वह दिन दूर नहीं जब भगवान मुस्कुराकर कहेंगे— 'वत्स! इस ब्रह्मांड का सृजन तो मैंने किया था, पर मेरे ही मंदिर का नियंत्रण अब किसी और के पास है। मैं भी दर्शन के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ।

और भक्त हाथ जोड़कर कहेगा— 'प्रभु! कृपा तो आप ही करना... बाकी फ़ाइल तो सरकार देख ही लेगी!

मंदिर में सरकार है, भक्त हुए लाचार।

दान चढ़े भगवान को, बैठे लें दरबार।

बैठे लें दरबार, तिजोरी किसकी होगी?

श्रद्धा रोए मौन, भला यह कैसी जोगी?

कहे 'मतवाला', सोचो यह कैसा व्यवहार,

भगवान हैं मेहमान, मंदिर में सरकार।

(विक्टोरिया, टेक्सास अमेरिका)

इतिहास

22 जुलाई का दिन भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है।22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इसके अलावा, इस तारीख के अन्य प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम इस प्रकार हैं:1933: अमेरिकी पायलट 'विली पोस्ट' ने 'विनी मे' (Winnie Mae) नामक विमान से अकेले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। 2003: इराक के मोसुल शहर में अमेरिकी सेना द्वारा की गई एक कार्रवाई में सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों—उदय और कुसै—को मार गिराया गया।

मनरेगा में काफी अनियमितताएं उजागर, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं, उठे सवाल

विश्व केसरी■

कवर्धा (जगदंबिका साहू)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कबीरधाम जिले में जारी लगातार प्रशासनिक आदेशों ने पंचायत एवं मनरेगा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के बार-बार तबादले, संलग्नीकरण और अतिरिक्त प्रभार देने की प्रक्रिया ने यह चर्चा तेज कर दी है कि कहीं यह पूरा खेल जवाबदेही तय होने से बचने और संभावित अनियमितताओं को फाइलों में दबाने का माध्यम तो नहीं बन गया है।

जिले में सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच जारी आदेशों पर नजर डालें तो प्रशासनिक स्थिरता पूरी तरह गायब दिखाई देती है। जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा जारी आदेश के तहत जनपद पंचायत बोड़ला में पदस्थ सहायक प्रोग्रामर दिलीप कुमार साहू को जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा भेजा गया, जबकि सहसपुर लोहारा में कार्यरत सहायक प्रोग्रामर नवीन तिर्की को बोड़ला में अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में सहसपुर लोहारा के कार्यक्रम अधिकारी (संविदा) सेवक कुमार चंद्रवंशी को प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए जिला पंचायत में संलग्न कर दिया गया।

सबसे अधिक चौंकाने वाला आदेश दिसंबर 2025 में सामने आया, जिसमें सहायक प्रोग्रामर दिलीप कुमार साहू को कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। एक के बाद एक जारी इन आदेशों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जिले में ऐसी कौन-सी परिस्थितियां निर्मित हो गई थीं, जिनके कारण कुछ ही महीनों में कई बार प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी पड़ी।

गौरतलब है कि राज्य मनरेगा परिषद द्वारा वर्ष 2018 में जारी आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जनपद पंचायत स्तर पर सहायक प्रोग्रामर की जिम्मेदारी तय है और यदि स्वीकृत राशि से अधिक व्यय, वित्तीय अनियमितता अथवा भुगतान में गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्यक्रम अधिकारी के साथ सहायक प्रोग्रामर भी समान रूप से जिम्मेदार होंगे। आदेश में यहां तक उल्लेख किया गया है कि अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद वर्ष 2022 में राज्य स्तर से एक और आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया कि कार्यक्रम अधिकारियों के प्रभार को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाए तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। बावजूद इसके कबीरधाम जिले में बार-बार किए गए संलग्नीकरण और अतिरिक्त प्रभारों ने इन आदेशों की मंशा पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मनरेगा के अंतर्गत जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्य संचालित होते हैं। नाली निर्माण, रिटर्निंग वाल ,डैम, स्टॉप डैम निर्माण शीत अन्य विकास कार्यों में भारी राशि खर्च की जाती है। ऐसे में प्रशासनिक स्थिरता का अभाव और लगातार प्रभार परिवर्तन किसी भी वित्तीय एवं तकनीकी जवाबदेही को प्रभावित कर सकता है। सूत्रों की मानें तो विभाग में लंबे समय से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भुगतान प्रक्रिया, मूल्यांकन, स्वीकृत राशि से अधिक व्यय और कार्य पूर्ण होने के बाद निरीक्षण को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में यदि अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रभार लगातार बदलते रहेंगे, तो किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाएगा। जांच के दौरान अधिकारी अपने कार्यकाल की सीमाओं का हवाला देकर जवाबदेही से बचने का प्रयास कर सकते हैं। प्रशासनिक हलकों में यह भी चर्चा है कि मनरेगा में जारी इस तरह के आदेशों से फाइलों की जवाबदेही बंट जाती है और किसी एक अधिकारी पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती। यही कारण है कि विभागीय कार्यप्रणाली पर संदेह गहराता जा रहा है। पंचायत विभाग में जारी इन आदेशों ने यह संकेत अवश्य दे दिया है कि जिले में मनरेगा की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह सामान्य नहीं है। यदि सब कुछ नियमानुसार चल रहा था तो फिर बार-बार तबादला और अतिरिक्त प्रभार देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वहीं यदि किसी स्तर पर अनियमितताएं थीं, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के बजाय केवल पदस्थापना बदलने तक ही मामला क्यों सीमित रहा।

मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, उसमें प्रशासनिक अस्थिरता और जवाबदेही का अभाव गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जिला प्रशासन और राज्य स्तर के अधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट करें कि लगातार जारी इन आदेशों के पीछे वास्तविक कारण क्या थे तथा यदि कहीं वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता हुई है तो संबंधित जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अन्यथा मनरेगा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही केवल कागजों तक सीमित होकर रह जाएगी।

सरसींवा से सराईपाली की सड़क बदहाल हालत में

विश्व केसरी■

सरसींवा (राकेश सोनी)। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरसीवां से सरायपाली मार्ग की बदहाल तस्वीरें लोगों की परेशानी बयां कर रही हैं। बरसात में यह सड़क कीचड़ और बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है। हालांकि सड़क निर्माण कार्य जारी है और सड़कों से गड्ढे भी भरे जा रहे हैं, लेकिन आवागमन करने वाले राहगीरों को रोजाना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सरसीवां से मातानाला और मातानाला से सरायपाली तक सड़क निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है और काम प्रगति पर है। इसके बावजूद पुराने मार्ग पर बने गहरे बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ हैं। बारिश के चलते सड़क पर जलभराव और कीचड़ से दोपहिया वाहन तो दूर, साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया है। आए दिन लोग फिसलकर गिर रहे हैं और दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। राहगीरों का कहना है कि बरसात के मौसम में इस मार्ग से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। जहां लोगों ने शासन-प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने और सड़कों पर हुएं बड़े बड़े गड्ढे को जल्द से जल्द मरम्मत कर बेहतर सड़क उपलब्ध कराने की मांग की है।

फिलहाल संबंधित ठेकेदार ने निर्माण कार्य जारी रखा है, लेकिन जब तक सड़क पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख पड़ रही हैं।

संक्षिप्त खबरें

जर्जर स्कूल भवन और बदहाल शौचालय के भरोसे नौनिहाल, जिम्मेदार मौन

विश्व केसरी■

कसडोल (प्रवीण कुमार)। सडोल(महाकोशल)विकासखंड कसडोल के अंतर्गत ग्राम बार स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल और प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है।यहाँ के सुलभ शौचालय साफ-सफाई के अभाव में बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुके हैं,जिसके कारण स्कूली बच्चों को भारी असुविधा हो रही है। शौचालय की दुर्दशा की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं को उठानी पड़ रही है।बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ दोनों ही स्कूलों के भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं।दीवारों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं,कई जगहों पर छत से पानी टपकता है और सालों से रंगरोगन तक नहीं कराया गया है,जिससे छात्र डर के साये में पढ़ने को मजबूर हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही स्कूल की मरम्मत और शौचालय को ठीक कराया जाए नहीं तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वही इस संबंध में बीईओ अरविंद ध्रुव को फोन किया तो फोन की घंटी बजती रही लेकिन फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा।

नगर पंचायत कसडोल में नवनियुक्त एल्डरमैनों ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ

शपथ ग्रहण समारोह
नगर पंचायत कसडोल के मनोनीत एल्डरमैन
शपथ ग्रहण समारोह में
पधारे समस्त अतिथियों का

विश्व केसरी■

कसडोल (प्रवीण कुमार)। नगर पंचायत कसडोल में नवनियुक्त मनोनीत एल्डरमैनों के पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय गौरीशंकर अग्रवाल रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष नागेश्वर साहू ने की। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. अजय राव (प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़) एवं डॉ. सुदीप दास मानिकपुरी (उपाध्यक्ष नगर पंचायत कसडोल) सहित नगर पंचायत के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। समारोह में नगर पंचायत कसडोल के नवनियुक्त एल्डरमैन गोटीलाल साहू, राजेंद्र श्रीवास एवं शीला वर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गौरीशंकर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व केवल पद की गरिमा बनाए रखना ही नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण, पारदर्शिता और जनविश्वास के साथ नगर के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाना भी है।

बिलासपुर का बढ़ा गौरव, डॉ. ललित मखीजा बने विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांताध्यक्ष

विश्व केसरी■

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक 19 एवं 20 जुलाई को छतरपुर, नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में बिलासपुर के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक एवं विनायक नेत्रालय के संचालक डॉ. ललित मखीजा को विश्व हिंदू परिषद, छत्तीसगढ़ प्रांत का प्रांताध्यक्ष घोषित किया गया। डॉ. मखीजा इससे पूर्व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं।

डॉ. ललित मखीजा को प्रांताध्यक्ष बनाए जाने से बिलासपुर का संगठनात्मक, सामाजिक एवं धार्मिक महत्व प्रदेश स्तर पर और अधिक सुदृढ़ हुआ है। विश्व हिंदू परिषद जैसे राष्ट्रव्यापी संगठन में बिलासपुर के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं समाजसेवी को यह महत्वपूर्ण दायित्व मिलना पूरे जिले के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे बिलासपुर के बढ़ते वर्चस्व, सामाजिक योगदान एवं संगठनात्मक सक्रियता का प्रतीक बताया।

23 जुलाई को निरस्त की गई चार मेमू यात्री ट्रेनें फिर से परिचालन प्रारंभ

विश्व केसरी■

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा-हथबंध स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग की कमीशनिंग हेतु नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्य के कारण दिनांक 23 जुलाई 2026 को कुछ यात्री गाड़ियों को निरस्त किया गया था।

रेल यात्रियों एवं विद्यार्थियों की सुविधा तथा उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2026 को निरस्त की गई निम्नलिखित यात्री गाड़ियों को रिस्टोर कर दिया गया है। अब ये सभी गाड़ियाँ अपने निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी।

रिस्टोर की गई गाडियां :- 23 जुलाई 2026 को गाडी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर को रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी।

23 जुलाई 2026 को गाडी संख्या 68734 बिलासपुर-कोरबा मेमू पैसेंजर को रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी।

23 जुलाई 2026 को गाडी संख्या 68733 कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर को रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी।

23 जुलाई 2026 को गाडी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर को रिस्टोर कर दी गई है उपरोक्त तिथि में यह गाड़ी अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी।

चंद्रा पार्क वेलफेयर सोसाइटी में 10 किलोवाट प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत ऊर्जा संयंत्र स्थापित

विश्व केसरी■

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं चंद्रा पार्क वेलफेयर सोसाइटी, (अपार्टमेंट) बृहस्पति बाजार, बिलासपुर द्वारा कॉमन मीटर (बी.पी.क्रमांक 1002089882) के अंतर्गत लिफ्ट, पानी के पंप एवं स्ट्रीट लाइट के संचालन हेतु 10 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया गया है।

अब इस सोलर प्लांट के माध्यम से सोसाइटी की साझा विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा से होगी। इससे उपभोक्ता क्रमांक 1002089882 के बिजली की खपत में कमी आने के साथ -साथ कॉमन एरिया के बिजली बिल में भी उल्लेखनीय बचत होगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि सौर ऊर्जा अपनाने से दीर्घकाल में ऊर्जा लागत कम होगी और निवासियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह पहल अन्य आवासीय समितियों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण एवं अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल सतत् विकास और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति सोसाइटी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह उपलब्धि केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है।

डॉ. अंकिता सिंह को मनोविज्ञान में पीएच.डी. की उपाधि

विश्व केसरी■

बिलासपुर (अमित मिश्रा)। शहर की काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एवं मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. अंकिता सिंह को एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा मनोविज्ञान (Psychology) विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक C/EC/Ph.D./Notification/2025-26/048 दिनांक 30 जून 2026 के अनुसार उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई।

डॉ. अंकिता सिंह, गौरी शंकर आर्य एवं श्रीमती मालती सिंह की सुपुत्री हैं। उन्होंने अपना शोधकार्य एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल एंड एलाइड साइंसेज़, एमिटी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर में डॉ. महेन्द्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर, के निर्देशन में सफलतापूर्वक पूर्ण किया। उनका शोध विषय ÒA Comparative Study Among Inter Role Conflict, Self-Efficacy, and Home Environment Between Homemakers and Employed Early Adulthood Females of Chhattisgarh 'रहा। यह शोध छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक वयस्क आयु वर्ग की गृहिणियों एवं कार्यरत महिलाओं के मध्य भूमिका संघर्ष, आत्म-प्रभावकारिता तथा पारिवारिक वातावरण के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है, जो महिला मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। वर्तमान में डॉ. अंकिता सिंह एक अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य संस्था में काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। वे पिछले आठ वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मनोवैज्ञानिक शोध, कर्मचारी कल्याण (Employee Well-being), संकट परामर्श (Crisis Counseling) तथा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। वर्ष 2021 में प्रारंभ हुई उनकी पीएच.डी. शोध यात्रा वर्ष 2026 में सफलतापूर्वक पूर्ण हुई।

जिला मुख्यालय में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों पर उठ रहे सवाल

विश्व केसरी■

संयुक्त जिला कार्यालय
बलौदाबाजार-भाटापारा
कलेक्टर कार्यालय

बलौदाबाजार (भुवन लाल)। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा 14 जुलाई 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट रूप से सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के संलग्नीकरण को तत्काल समाप्त कर उन्हें मूल पदस्थ संस्था एवं कार्यालय में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने, अन्यथा जुलाई माह का वेतन रोकने और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।

इसके बावजूद बलौदाबाजार जिला मुख्यालय सहित विभिन्न ब्लॉक मुख्यालयों में वर्षों से जमे कर्मचारी आज भी अपने मूल संस्थानों में लौटने के बजाय कार्यालयों में डटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय एवं विकासखंड शिक्षा कार्यालयों से कई गैर शैक्षणिक कर्मचारी लंबे समय से संलग्नीकरण के नाम पर अन्य कार्यालयों में कार्यरत हैं। संचालनालय के सख्त आदेश के बाद भी इन्हें मूल संस्थाओं में भेजने की कोई गंभीर पहल दिखाई नहीं दे रही है। इससे यह सवाल उठने लगा है कि आखिर शासन के आदेशों का पालन कराने में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग क्यों उदासीन बना हुआ है।

विडंबना यह है कि एक ओर कई स्कूल और मूल संस्थाएं कर्मचारियों की कमी से प्रभावित हैं, वहीं दूसरी ओर जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में कर्मचारियों की भीड़ बनी हुई है। इससे शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। शासन द्वारा जारी आदेश का उद्देश्य स्कूलों और मूल कार्यालयों में व्यवस्था को सुचारू बनाना था, लेकिन जिले में इसके विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। आदेश में स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि मूल संस्था में उपस्थित नहीं होना और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करना कदाचार की श्रेणी में आएगा। इसके बावजूद अब तक किसी कर्मचारी का वेतन रोकने अथवा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की कोई सूचना सामने नहीं आई है।

विभागीय सूत्रों की मानें तो कुछ कर्मचारियों को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि संचालनालय के निर्देश जिले में बेअसर साबित हो रहे हैं और संलग्नीकरण की व्यवस्था पूर्ववत जारी है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला शासन के आदेशों की खुली अवहेलना का बड़ा उदाहरण बन सकता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग नियमों का पालन कराते हैं या फिर जिला मुख्यालय में वर्षों से जमे कर्मचारियों को संरक्षण देने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

85 छात्राओं को मिली नि:शुल्क साइकिल

विश्व केसरी■

सरसींवा (राकेश सोनी)। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धोबनी में मंगलवार को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं की 85 छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरित की गई। साइकिल मिलते ही छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। छात्राओं ने बताया कि अब उन्हें विद्यालय आने-जाने में सुविधा होगी, समय की बचत होगी और वे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी।कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके बाद सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। अतिथियों ने छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला तथा अनुशासन, नियमित अध्ययन और कठिन परिश्रम के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तोषण लाल साहू, ग्राम पंचायत धोबनी के सरपंच राजीव लोचन साहू, भाजपा किसान मोर्चा मंडल सरसीवा के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, हरीश साहू, रोहित साहू, जगमोहन लाल साहू, प्रहलाद साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अभिभावक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रभारी प्राचार्य मुकेश कुमार नारंग ने छात्राओं को शिक्षा का महत्व बताते हुए नियमित अध्ययन और अनुशासित जीवन अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान विद्यालय छात्र संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों को उनके दायित्वों की शपथ भी दिलाई गई। विद्यालय परिवार की ओर से हेमलता टोप्पो, लक्ष्मीकांत पटेल, मंशाराम मनहर, मोहन लाल साहू, नरोत्तमदास मानिकपुरी, जैन कुमार चौधरी, रत्तु राम साहू, मिथलेश कुमार ध्रुव, वीरेंद्र मनहरे आदि शामिल रहे।

भारत में विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड क्षमता 57,443 मेगावाट पहुंची, हुआ 106 अरब यूनिट बिजली का उत्पादनः सरकार

विश्व केसरी

नई दिल्ली। देश में विंड एनर्जी (पवन ऊर्जा) का दायरा लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि देश में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स की कुल इंस्टॉल्ड क्षमता बढ़कर 57,443 मेगावाट हो गई है। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इन परियोजनाओं से 106 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान विंड एनर्जी से बिजली उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (जीडब्ल्यूईसी) रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन के मामले में भारत दुनिया भर में चौथे स्थान पर रहा।

सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेषकर विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के माध्यम से नई ट्रांसमिशन लाइनें और सब-स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का सुचारु प्रसारण सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, 30 जून 2025 तक चालू हुई सौर और विंड एनर्जी परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय बिजली बिक्री पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क में छूट दी गई है। इसके बाद शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध शुल्क व्यवस्था लागू की गई है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक प्लान तैयार किया गया है। साथ ही, इस सेक्टर में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को ऑटोमैटिक रूट के तहत अनुमति दी गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा की खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2029-30 तक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ) और रिन्यूएबल कंजम्प्शन ऑब्लिगेशन (आरसीओ) का लक्ष्य भी तय किया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत आने वाले सभी निर्धारित उपभोक्ताओं के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा, और उल्लंघन की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान भी रहेगा।

सरकार ने ग्रिड से जुड़े सौर, विंड, विंड-सोलर हाइब्रिड और फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) परियोजनाओं से बिजली खरीद के लिए संशोधित मानक बोली दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

ई20 पेट्रोल से पुराने वाहनों में माइलेज थोड़ा घट सकता है, लेकिन इंजन को नुकसान का कोई सबूत नहींः सरकार

विश्व केसरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि ई20 पेट्रोल (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) के इस्तेमाल से ई10 पेट्रोल के लिए डिजाइन किए गए कुछ पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता (माइलेज) में मामूली कमी आ सकती है। हालांकि, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या वाहनों में खराबी आने का कोई सत्यापित (वेरिफाइड) प्रमाण नहीं मिला है।

राज्यसभा में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि ई10 के लिए डिजाइन किए गए पुराने वाहनों में माइलेज में होने वाली कमी आमतौर पर करीब 3 से 5 प्रतिशत तक ही सीमित रहती है।

उन्होंने कहा कि किसी वाहन का माइलेज केवल पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ड्राइविंग की आदत, वाहन का रखरखाव, टायर प्रेशर, व्हील अलाइनमेंट और एयर कंडीशनर (एसी) के उपयोग जैसे कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है।

सुरेश गोपी ने कहा, 'ई10 के लिए डिज़ाइन किए गए कुछ पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता में होने वाली कमी सामान्यतः मामूली (करीब 3-5 प्रतिशत) होती है।'

उन्होंने आगे कहा, 'कुछ पुराने वाहनों में माइलेज में हल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन ई20 पेट्रोल के कई फायदे भी हैं। इसमें अधिक ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी-नॉक प्रदर्शन, बेहतर दहन क्षमता और अधिक स्मूथ एक्सीलरेशन मिलता है।

इस बीच, इसी महीने 7 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ई20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों पर आलोचकों को चुनौती दी थी।

उन्होंने कहा था कि यदि 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से किसी वाहन को नुकसान हुआ हो, तो उसका एक भी उदाहरण सामने लाकर दिखाया जाए। साथ ही उन्होंने माइलेज कम होने और अन्य दावों को 'पेड कैंपेन' का हिस्सा बताया था।

भारत-नेपाल व्यापार संबंधों में बड़ी उपलब्धि, कोलकाता पोर्ट के जरिए बिराटनगर पहुंचा कैनोला का पहला शिपमेंट

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में कोलकाता पोर्ट से भारत के जोगबानी इंडियन कस्टम यार्ड के जरिए कैनोला के दाने का पहला शिपमेंट नेपाल के बिराटनगर में मौजूद कस्टम यार्ड पहुंच गया है।

नेपाल में मौजूद भारतीय दूतावास ने इसे भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध बड़ी उपलब्धि बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया कि 20 जुलाई 2026 को कोलकाता पोर्ट से भारतीय कस्टम यार्ड, जोगबनी के रास्ते कैनोला अनाज की पहली खेप नेपाल के बिराटनगर स्थित कस्टम यार्ड पहुंची। यह नेपाल-भारत ट्रांजिट संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन संबंधी लेटर ऑफ एक्सचेंज पर नवंबर 2025 में हस्ताक्षर होने का परिणाम है।

पोस्ट में आगे कहा गया कि क्रॉस-बॉर्डर कार्गो ट्रेन सेवाएं लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करेंगी और भारत-नेपाल के बीच व्यापार को और बढ़ावा देंगी।

पिछले वर्ष नेपाल-भारत ट्रांजिट संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन के बाद नेपाल को बिराटनगर एकीकृत जांच चौकी (आईसीपी) के माध्यम से बल्क और कंटेनर दोनों प्रकार की रेल माल ढुलाई सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति मिली थी। इसके बाद भारतीय सहयोग से निर्मित बिराटनगर आईसीपी पर पहली बार सीधे मालगाड़ी पहुंची है।

बिराटनगर कस्टम्स कार्यालय के मुख्य सीमा शुल्क अधिकारी उमेश श्रेष्ठ ने आईएएनएस से कहा, 'स्वस्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले कैनोला अनाज से भरे 40 कंटेनरों वाली मालगाड़ी सोमवार को आईसीपी पहुंची। यह खेप कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीओएनसीओआर) द्वारा संचालित मालगाड़ी से लाई गई। सभी कंटेनरों में इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (ईसीटीएस) लगाया गया था, जिससे पूरे मार्ग के दौरान माल की निगरानी की जा सकी। नेपाल के कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावास ने पहले जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया था कि यह मालगाड़ी 17 जुलाई को कोलकाता बंदरगाह से रवाना हुई थी। इसमें 40 उच्च क्षमता वाले कंटेनर थे, जिन्हें बिराटनगर आईसीपी स्थित कस्टम्स यार्ड तक पहुंचाया गया।

सोने और चांदी में उछाल, मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की बढ़ी मांग

विश्व केसरी

मुंबई । सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को एक प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई। इसकी वजह मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ना है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अगस्त 2026 का कॉन्ट्रैक्ट अपनी पिछली क्लोजिंग 1,42,883 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,44,852 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला।

सुबह 9:47 पर यह 1,517 रुपए या 1.06 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,44,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।

अब तक के कारोबार में सोने ने 1,44,311 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,44,883 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर बनाया है और दिखाता है कि खुलने के बाद सोने एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है।

चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,23,779 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2,26,568 रुपए प्रति किलो पर खुला।

फिलहाल यह 2,259 रुपए या 1.01 प्रतिशत की मजबूती के साथ 2,26,038 रुपए प्रति किलो पर खुला। अब तक के कारोबार में चांदी ने 2,25,885 रुपए का न्यूनतम स्तर और 2,26,892 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ है।

जानकारों ने कहा कि इस तेजी की वजह अमेरिका-ईरान में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ना है। साथ ही, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने से भी कीमती धातुओं को सपोर्ट मिल रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। खबर लिखे जाने तक कॉमेक्स पर सोना 1.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,133 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.50 प्रतिशत की मजबूती के साथ 60 डॉलर प्रति औंस के करीब था।

दूसरी तरफ, अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध के चलते मध्य पूर्व में तनाव हुआ है।

अमेरिका ने लगातार 11वें दिन ईरान पर हमले किए, जिसमें उसकी ड्रोन भंडारण सुविधाओं, समुद्र में हमला करने की क्षमताओं और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।

वहीं, ईरान भी मध्यू पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है।

एयर इंडिया में दिख रही मजबूत प्रगति, एजीएम से पहले बोली सिंगापुर एयरलाइंस

विश्व केसरी

नई दिल्ली। एयर इंडिया में करीब 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली सिंगापुर एयरलाइंस (एसआईए) ने कहा है कि टाटा ग्रुप एयरलाइन के बदलाव में मजबूत प्रगति देखने को मिली है। यह साझेदारी उसकी लंबी अवधि की मल्टी-हब रणनीति का हिस्सा है।

सिंगापुर एयरलाइंस की ओर से यह बयान शेयरधारकों और निवेशकों की ओर से 24 जुलाई को होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग (एजीएम) से पहले पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया है।

सवाल के जवाब में सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा कि उसने समीक्षा की आवश्यकता दर्शाने वाले संकेत मिलने के बाद औपचारिक इम्पेयरमेंट असेसमेंट किया, लेकिन निष्कर्ष यह निकाला कि एयर इंडिया में उसके निवेश के मूल्य में किसी प्रकार की कटौती करने की जरूरत नहीं है।

सिंगापुर एक्सचेंज में दाखिल दस्तावेज के अनुसार, सिंगापुर एयरलाइंस ने दोहराया कि एयर इंडिया में उसकी 25.1 प्रतिशत हिस्सेदारी उसकी लंबी अवधि की मल्टी-हब रणनीति का अहम हिस्सा बनी हुई है। कंपनी ने इसके पीछे भारत के विमानन क्षेत्र की मजबूत विकास संभावनाओं का हवाला दिया।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइन ने एयर इंडिया के भविष्य के फंडिंग, भू-राजनीतिक जोखिम, डिजिटल सेवाओं और ग्राहक अनुभव से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए।

सिंगापुर एयरलाइंस ने स्वीकार किया कि एयर इंडिया अभी भी कई चर्चित चुनौतियों का सामना कर रही है। इनमें भारतीय रुपए का अवमूल्यन, सप्लाई चेन में व्यवधान, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का बंद होना और जून 2025 का विमान हादसा शामिल है, जिसमें 260 लोगों की जान गई थी।

इन चुनौतियों के बावजूद सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा कि एयर इंडिया ने कई प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत प्रगति की है। इनमें ग्राहक अनुभव, विमान बेड़े और नेटवर्क का विस्तार, परिचालन प्रदर्शन तथा ग्राउंड और इन-फ्लाइट सेवाओं में सुधार शामिल हैं।

सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा कि यदि भविष्य में एयर इंडिया अतिरिक्त पूंजी की मांग करती है, तो उसका निदेशक मंडल समूह की अपनी पूंजी आवश्यकताओं और एयर इंडिया की कारोबारी रणनीति को ध्यान में रखते हुए उस अनुरोध का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगा।

हालांकि, एयरलाइन ने उन खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिनमें कहा गया था कि एयर इंडिया ने अक्टूबर 2025 में 1.1 अरब डॉलर की अतिरिक्त पूंजी निवेश की मांग की थी।

सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा, 'अपनी लेखा नीति के अनुरूप, समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एयर इंडिया में अपने निवेश का इम्पेयरमेंट के किसी भी संकेत के लिए आकलन करता है और जब भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि एयर इंडिया में उसके निवेश का मूल्य प्रभावित हो सकता है, तब औपचारिक इम्पेयरमेंट परीक्षण किया जाता है।

सिंगापुर एयरलाइंस ने यह भी कहा कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एयर इंडिया के निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिससे एयरलाइन एयर इंडिया को रणनीतिक मार्गदर्शन और विमानन उद्योग से जुड़ी विशेषज्ञता प्रदान कर सकती है।

बंधन बैंक के लिए उच्च परिचालन लागत बनी चुनौती, शेयर 17 प्रतिशत से अधिक लुढ़का

विश्व केसरी

मुंबई। बंधन बैंक का शेयर बुधवार को 17 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया। इसकी वजह बैंक की ओर से उच्च परिचालन लागत और कम मार्जिन के चलते वित्त वर्ष 27 के लिए आरओए (रिटर्न-ऑन-एसेट) आउटलुक को कम करना है।

नतीजों के बाद बैंक ने वित्त वर्ष 27 की चौथी तिमाही के लिए आरओए आउटलुक को 40 आधार अंक कम करके 1.2-1.4 प्रतिशत कर दिया, जो कि पहले 1.6-1.8 प्रतिशत था।

इसमें 30 आधार अंक का योगदान कम शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और 10 आधार अंक का योगदान उच्च परिचालन लागत का है।

दोपहर 12 बजे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर बंधन बैंक का शेयर 17.44 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 172.40 रुपए पर था। इनका इंट्राडे लो 171.56 रुपए रहा है। हालांकि, निजी बैंक के वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के नतीजे अच्छे रहे थे। बैंक का मुनाफा करीब 35 प्रतिशत बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 372 करोड़ रुपए था।

इस दौरान बैंक की शुद्ध ब्याज आय सालाना आधार पर 6 प्रतिशत बढ़कर 2,921 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं, शुद्ध ब्याज मार्जिन 6.2 प्रतिशत रहा है।

एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला। बैंक का सकल ग्रॉस एनपीए अनुपात पिछली तिमाही के 3.27 प्रतिशत से घटकर 3.15 प्रतिशत हो गया, जबकि नेट एनपीए 0.97 प्रतिशत से घटकर 0.93 प्रतिशत पर आ गया।

वहीं, प्रोविजन में तेज गिरावट आई और यह एक साल पहले के 1,147 करोड़ रुपए से घटकर 683 करोड़ रुपए रह गया, जिससे बैंक की आय वृद्धि को समर्थन मिला।

भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 690 अंक या 0.89 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 76,790 और निफ्टी 188 अंक या 0.80 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 23,999 पर था।

बैंकिंग शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। निफ्टी बैंक 1.30 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 57,081 पर था।

बर्नस्टीन ने पेटीएम के फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को बताया 'स्टार परफॉर्मर', आय 45 प्रतिशत बढ़ी

विश्व केसरी

नई दिल्ली। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने कहा है कि फिनटेक कंपनी पेटीएम का फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार वित्त वर्ष 27 की जून तिमाही में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेगमेंट रहा। इस कारोबार की आय सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 814 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। इसका प्रमुख कारण क्रेडिट और अन्य वित्तीय उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग में लगातार सुधार रहा।

ब्रोकरेज ने पेटीएम पर अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखते हुए शेयर का टारगेट प्राइस 1,500 रुपए रखा है।

बर्नस्टीन के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के नतीजों ने उसके उस निवेश सिद्धांत को मजबूत किया है, जिसके मुताबिक कंपनी में आय वृद्धि और ऑपरेटिंग लीवरेज के दम पर गैर-रैखिक मुनाफे की वृद्धि देखने को मिलेगी।

तिमाही के दौरान कंपनी की आय सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़ी, जबकि अप्रत्यक्ष खर्च केवल 6 प्रतिशत बढ़े। इसके चलते ईबीआईटीडीए में 182 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, पीआईडीएफ (पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) प्रोत्साहन को हटाकर तुलना करने पर ईबीआईटीडीए में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी हुई।

ब्रोकरेज ने मजबूत वृद्धि के बावजूद लागत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी पेटीएम की सराहना की। प्लेटफॉर्म निर्माण से जुड़ी लागत सालाना आधार पर 3 प्रतिशत घटी, जबकि कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नए उत्पादों के विकास में निवेश जारी रखा। बर्नस्टीन का कहना है कि इससे इस सकारात्मक रुझान के लंबे समय तक बने रहने का भरोसा और मजबूत हुआ है।

भुगतान कारोबार का प्रदर्शन भी मजबूत रहा। मर्चेंट जीएमवी सालाना आधार पर 31 प्रतिशत बढ़कर 7.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि उपभोक्ता यूपीआई भुगतान मूल्य में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो उद्योग की औसत वृद्धि दर से दोगुने से भी अधिक है।

मासिक लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या भी एक साल पहले के 7.4 करोड़ से बढ़कर करीब 8 करोड़ हो गई। बर्नस्टीन ने इसे ग्राहकों की बढ़ती सक्रियता और जुड़ाव का संकेत बताया।

ब्रोकरेज ने कहा कि इस तिमाही की प्रमुख सकारात्मक बातें मजबूत भुगतान वॉल्यूम, लागत पर कड़ा नियंत्रण और वित्तीय सेवाओं के कारोबार में तेज वृद्धि रहीं।

बर्नस्टीन ने कहा, 'लागत अनुशासन हमारी उम्मीद के अनुरूप जारी है, इसलिए कंपनी की आय वृद्धि की दिशा मजबूत बनी हुई है। ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी के लेंडिंग कारोबार से जुड़े संकेतक, जैसे अपेक्षित क्रेडिट हानि और दोबारा ऋण लेने वाले ग्राहकों के आंकड़े भी अच्छी स्थिति में हैं। बर्नस्टीन ही नहीं, अन्य ब्रोकरेज भी पेटीएम को लेकर सकारात्मक हैं।

मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया? तीनों में क्या है फर्क, किस बीमारी में कौन से लक्षण दिखते हैं और कैसे करें बचाव, जानिए

बरसात का मौसम आते ही मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है. मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की शुरुआत अक्सर तेज बुखार और शरीर दर्द से होती है, इसलिए लोग इन्हें एक जैसा समझ लेते हैं. जबकि इन तीनों के कारण, लक्षण और इलाज अलग-अलग होते हैं. सही समय पर पहचान और डॉक्टर से जांच कराना गंभीर परेशानी से बचा सकता है. आइए जानते हैं तीनों बीमारियों में क्या अंतर है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

बरसात का मौसम गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन इसके साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है. इस मौसम में जगह-जगह पानी जमा होने लगता है, जिससे मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल बन जाता है. यही मच्छर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं. परेशानी की बात यह है कि इन तीनों की शुरुआत लगभग एक जैसी होती है. तेज बुखार, बदन दर्द, कमजोरी और सिरदर्द जैसे लक्षण होने पर कई लोग समझ नहीं पाते कि आखिर कौन सी बीमारी है. ऐसे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि समय रहते जांच कराई जा सके और इलाज शुरू हो सके. हालांकि इन तीनों बीमारियों में कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो इन्हें एक-दूसरे से अलग पहचानने में मदद करते हैं.

मलेरिया किस वजह से होता है

मलेरिया एक परजीवी से होने वाली बीमारी है. यह संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है. अगर समय पर इलाज न मिले तो यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है. इसलिए मलेरिया को हल्के में लेना ठीक नहीं माना जाता.

डेंगू कैसे फैलता है

डेंगू एक वायरल बीमारी है. यह संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलती है. यह मच्छर आमतौर पर दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है. कई लोगों में डेंगू हल्का रहता है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर रूप ले सकता है और मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है.

चिकनगुनिया का कारण क्या है

चिकनगुनिया भी वायरस से होने वाली बीमारी है और यह भी एडीज मच्छर के काटने से फैलती है. इसकी सबसे खास पहचान जोड़ों में होने वाला तेज दर्द है. कई लोगों में बुखार उतरने के बाद भी कई हफ्तों या महीनों तक जोड़ों का दर्द बना रह सकता है.

मलेरिया के लक्षण कैसे पहचानें

मलेरिया में तेज बुखार अक्सर एक निश्चित अंतराल पर आता है. इसके साथ ठंड लगना, बहुत ज्यादा पसीना आना, सिरदर्द, शरीर दर्द, कमजोरी, उल्टी या मतली जैसी परेशानी हो सकती है. कई मरीजों को बुखार उतरने के बाद भी काफी थकान महसूस होती है.

डेंगू के लक्षण क्या होते हैं

डेंगू में अचानक तेज बुखार आता है. इसके साथ आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द, सिरदर्द, उल्टी, मतली और त्वचा पर लाल चकत्ते दिखाई दे सकते हैं. गंभीर डेंगू में पेट में तेज दर्द, बार-बार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून आना, सांस लेने में परेशानी और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण भी हो सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

चिकनगुनिया के लक्षण किस तरह अलग हैं

चिकनगुनिया में भी तेज बुखार आता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान हाथ, कलाई, घुटनों, टखनों और पैरों के जोड़ों में होने वाला तेज दर्द है. कई मरीजों को सिरदर्द, शरीर दर्द, थकान और त्वचा पर चकत्ते भी हो सकते हैं।

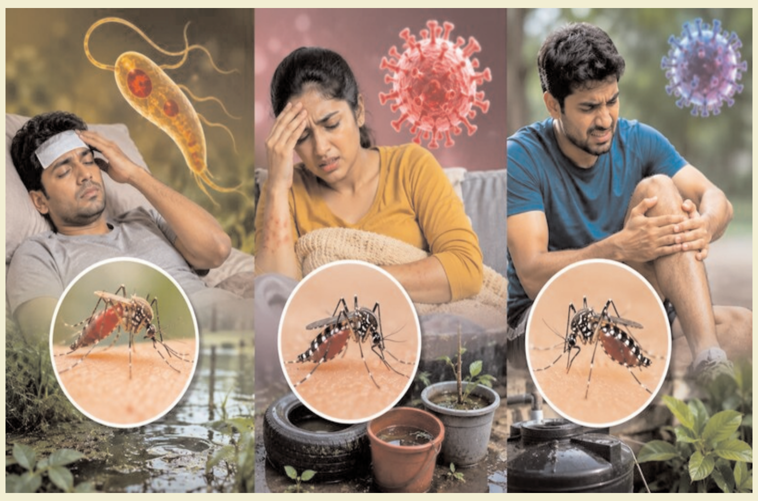

मैदा कैसे बनता है? क्यों कहा जाता है सफेद जहर, डॉक्टर ने बताया ज्यादा मैदा खाने के नुकसान

इसमें कोई दोराय नहीं कि मैदे को सफेद जहर कहा जा सकता है. क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाने पर यह मोटापा, डायबिटीज, पाचन संबंधी समस्याओं और दिल की बीमारियों जैसी दिक्कतों से जुड़ा होता है. डॉक्टर बताते हैं कि ये असल में जहर नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसका सेवन जानलेवा बीमारियों के जोखिम को बढ़ता है. इसलिए इसका सेवन संभलकर करना जरूरी है.

मैदा कई घर के खाने में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम चीजों में से एक है, जैसे ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, पिज्जा, नूडल्स, समोसे और कई तरह के पैक्ड स्नैक्स. इससे बनी खाने की चीजें मुलायम बनती है और साथ ही ये फूड्स जल्दी खराब भी नहीं होते. यही कारण है कि फूड इंडस्ट्री में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है. लेकिन सेहत के लिहाज से देखा जाए तो ज्यादा मैदा खाना हानिकारक होता है.

सेक्टर-88 में स्थित यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर डायरेक्टर डॉ. जयंत ठाकुरिया बताते हैं कि मैदा कोई जहरीली चीज नहीं है, लेकिन रिफाइंड आटे से बनी चीजें खाने से लाइफस्टाइल से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है. ऐसे में जरूरी है कि रिफाइंड गेहूं का आटा या मैदा से बने फूड प्रोडक्ट का सेवन कम करें.

कैसे बनता है मैदा?

एक्सपर्ट बताते हैं कि मैदा के इस्तेमाल से सबसे बड़ा खतरा इसके रिफाइंड होने के तरीके से जुड़ा है. रिफाइनिंग की प्रक्रिया में गेहूं के दाने के बाहरी हिस्से अंकुर को हटा दिया जाता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि दाने के इस हिस्से में काफी मात्रा में नुट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फाइबर, विटामिन, मिनरल और हेल्दी फैट. इसके बाद जो बचता है, वह ज्यादातर स्टार्च होता है. इसका मतलब है कि मैदा बस पेट भरने का एहसास देता है, लेकिन इसमें इंसानी शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते है।

सेहत के लिये केला है बहुत ही फायदेमंद, जानिये इसके फूल की हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनाने का तरीका

केले के फूल की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. दक्षिण भारत, बिहार, बंगाल में इसे पसंद किया जाता है. इसे बनाने की विधि और सामग्री यहां दी गई है. जिससे आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं.

केला केवल अपने फल के लिए ही नहीं, बल्कि इसके फूल के लिए भी जाना जाता है. केले का फूल, जिसे कई जगहों पर बनाना ब्लॉसम भी कहा जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इससे बनने वाली सब्जी का स्वाद बेहद लाजवाब होता है. दक्षिण भारत, बिहार, बंगाल और पूर्वी भारत के कई राज्यों में केले के फूल की सब्जी बड़े चाव से खाई जाती है. यदि आप कुछ अलग और पौष्टिक बनाना चाहते हैं, तो केले के फूल की सब्जी एक बेहतरीन विकल्प है.

सबसे पहले केले के फूल की बाहरी गहरे रंग की पत्तियां हटाएं. अंदर के नरम हिस्से को बारीक काट लें. कटे हुए फूलों को नमक और हल्दी मिले पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें. इससे उनका कसैलापन कम हो जाता है और रंग भी काला नहीं पड़ता.

केले के फूल को नमक और हल्दी मिले पानी में कितनी देर भिगोना चाहिए?

इसके बाद फूल को साफ पानी से धोकर 10 मिनट तक उबाल लें. फिर पानी छानकर अलग रख दें.

बनाने की विधि

एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर जीरा डालें और चटकने दें. अब प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनें।

पुरुषों के लिए बेस्ट मानसून हेयरस्टाइल: बारिश में भी रहेगा स्टाइल, नहीं दिखेंगे बिखरे बाल

बारिश का मौसम आते ही सिर्फ कपड़ों और जूतों की ही नहीं, बल्कि हेयरस्टाइल की भी चिंता बढ़ जाती है. घर से निकलते समय बाल चाहे जितने अच्छे से सेट किए हों, कुछ ही देर में नमी और पसीने की वजह से उनका लुक पूरी तरह बदल जाता है. खासकर पुरुषों के लिए यह परेशानी आम है, क्योंकि मानसून में लंबे या ज्यादा स्टाइल किए गए बाल जल्दी चिपचिपे और बेजान दिखने लगते हैं. ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कौन-सा हेयरस्टाइल अपनाया जाए जो कम देखभाल में भी अच्छा लगे और पूरे दिन साफ-सुथरा दिखाई दे. आइए जानते हैं पुरुषों के लिए ऐसे ही कुछ शानदार मानसून हेयरस्टाइल आइडियाज, जो इस मौसम में स्टाइल और सुविधा दोनों का बेहतरीन संतुलन बनाते हैं.

मानसून में छोटे बाल क्यों हैं बेहतर विकल्प? बारिश के मौसम में हवा में नमी काफी ज्यादा होती है. इसका असर सबसे पहले बालों पर दिखाई देता है. लंबे बाल जल्दी फ्रिज़ी हो जाते हैं, जबकि छोटे बाल जल्दी सूख जाते हैं और उन्हें संभालना भी आसान रहता है. यही वजह है कि इस मौसम में हल्के और क्लीन हेयरकट ज्यादा पसंद किए जाते हैं. अगर आपकी स्कैल्प ऑयली रहती है, तो छोटे बालों में पसीना और गंदगी भी कम जमा होती है. इससे बाल ज्यादा फ्रेश और साफ नजर आते हैं.

फेड कट है सबसे पसंदीदा विकल्प स्टाइलिश भी, आसान भी- फेड कट पिछले कुछ सालों से लगातार ट्रेंड में बना हुआ है. इसमें साइड के बाल छोटे रखे जाते हैं और ऊपर हल्की लंबाई छोड़ी जाती है. यह हेयरस्टाइल बारिश के मौसम में भी आसानी से सेट हो जाता है और ज्यादा मेहनत नहीं मांगता. ऑफिस जाने वाले युवाओं से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक, यह हेयरकट लगभग हर फेस शेप पर अच्छा लगता है.

क्रू कट देगा स्मार्ट लुक अगर आप सुबह बाल सेट करने में ज्यादा समय नहीं देना चाहते, तो क्रू कट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसमें बाल काफी छोटे रहते हैं, इसलिए बारिश या पसीने का असर कम दिखाई देता है. यह हेयरस्टाइल उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो हेलमेट पहनकर रोजाना यात्रा करते हैं.

टेक्सचर्ड क्रॉप का बढ़ रहा ट्रेंड आजकल टेक्सचर्ड क्रॉप भी काफी पसंद किया जा रहा है. इसमें ऊपर के बालों को हल्का टेक्सचर दिया जाता है, जिससे बिना ज्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाए भी बाल आकर्षक दिखते हैं. यह हेयरस्टाइल युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि यह कैजुअल और प्रोफेशनल दोनों लुक में फिट बैठता है.

साइड पार्ट हेयरस्टाइल भी है अच्छा विकल्प जिन लोगों को क्लासिक लुक पसंद है, वे साइड पार्ट हेयरस्टाइल चुन सकते हैं. बस ध्यान रखें कि बाल बहुत लंबे न हों. हल्की लंबाई के साथ साइड पार्ट मानसून में भी साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है. हल्के मैट फिनिश वाले हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से यह स्टाइल लंबे समय तक बना रह सकता है

बज कट रहेगा सबसे कम मेंटेनेंस वाला अगर आपको बिल्कुल झंझट पसंद नहीं है, तो बज कट सबसे आसान विकल्प माना जाता है. इसमें बाल बहुत छोटे रखे जाते हैं, जिससे बारिश, पसीना या नमी का ज्यादा असर नहीं पड़ता. जिम जाने वाले या ज्यादा आउटडोर काम करने वाले पुरुषों के लिए यह हेयरकट काफी सुविधाजनक रहता है.

मानसून में हेयरस्टाइल के साथ इन बातों का रखें ध्यान सिर्फ अच्छा हेयरकट करवाना ही काफी नहीं होता।

केले के फूल से बनाएं ऐसा कुरकुरा वड़ा, स्वाद चखते ही समोसा-पकौड़ा भूल जाएंगे! हर कोई मांगेगा दोबारा

केले के फूल का वड़ा दक्षिण भारत की पारंपरिक और स्वादिष्ट रेसिपी है. चना दाल और मसालों से तैयार यह स्नैक कुरकुरा होने के साथ पौष्टिक भी माना जाता है. शाम की चाय या किसी खास मौके पर इसे आसानी से घर में बनाया जा सकता है.

शाम होते ही अक्सर मन कुछ कुरकुरा और स्वादिष्ट खाने का करता है. ऐसे में ज्यादातर लोग समोसा, पकौड़े या कटलेट बना लेते हैं, लेकिन अगर इस बार कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं तो केले के फूल से बनने वाला वड़ा एक शानदार विकल्प हो सकता है. दक्षिण भारत की यह पारंपरिक रेसिपी अब देशभर के घरों में पसंद की जा रही है. खास बात यह है कि इसमें स्वाद के साथ पोषण भी भरपूर मिलता है. केले का फल तो लगभग हर घर में खाया जाता है, लेकिन इसके फूल का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं. जबकि केले का फूल कई पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है.

तमिलनाडु में इसे 'वझाईपू वड़ाई' के नाम से जाना जाता है और त्योहारों, पारिवारिक समारोहों या खास मौकों पर इसे बड़े चाव से बनाया जाता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम यह वड़ा चाय, नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है, अगर आप अपनी किचन में नई रेसिपी आजमाना पसंद करते हैं, तो यह डिश आपके परिवार की नई फेवरेट बन सकती है.

केले के फूल का वड़ा क्यों है खास?

केले के फूल का वड़ा सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पौष्टिकता के कारण भी जाना जाता है।

गोरम घाट घूमने से पहले जरूर जान लें ये नियम! छोटी सी लापरवाही करा सकती है ?5100 का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई

राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, जिसे 'मिनी कश्मीर' भी कहा जाता है, हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित करता है. लेकिन यहां घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. यदि कोई पर्यटक प्रतिबंधित क्षेत्रों में गंदगी फैलाता है, प्लास्टिक का अनुचित उपयोग करता है या स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित पर्यावरण एवं पर्यटन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ ?5100 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई और जेल की नौबत भी आ सकती है. इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों की जानकारी जरूर लें, स्वच्छता बनाए रखें और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण करें.

अगर आप भी इस मौसम में राजस्थान के 'मिनी कश्मीर' यानी गोरम घाट की वादियों का रुख कर रहे हैं... तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है. गोरम घाट के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण को बचाने के लिए ग्राम पंचायत काछबली और वन विभाग ने सख्ती बरतने का फैसला किया है. जंगल के भीतर किसी भी तरह का नशा, मदिरा, मांस ले जाना और हुड़दंग मचाना अब पूरी तरह से गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है. नियम तोड़ने पर 5,100 का भारी-भरकम जुर्माना लगेगा.

बारिश के बाद गौरमघाट में बडी संख्या के अंदर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है उसी के तहत कई बार यहां अवैध गतिविधियां देखने को मिलती है जिसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है ताकि प्रकृति को किसी तरह का नुकसान नही पहुंचे और किसी तरह का हादसा भी न हो.

इसलिए कहा जाता है मिनी कश्मीर

गोरम घाट राजस्थान के सबसे खूबसूरत और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे अरावली की पहाड़ियों का 'मिनी कश्मीर' भी कहा जाता है. यहाँ का मुख्य आकर्षण चारों तरफ फैली हरी-भरी पहाड़ियाँ, कल-कल बहते प्राकृतिक झरने और यहाँ से गुजरने वाली हेरिटेज ट्रेन है. पर्यटक यहाँ प्रकृति की गोद में शांति और सुकून के पल बिताने आते हैं. यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के बेहतरीन अवसर मिलते हैं. प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ का शांत वातावरण और झरने का मनमोहक दृश्य एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है.

इस बार न करे ऐसी गलती

गोरम घाट एक संरक्षित और पवित्र प्राकृतिक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना हर पर्यटक की जिम्मेदारी है. क्षेत्र में शराब (मदिरा) पीना, मांस या मांसाहारी भोजन करना और किसी भी प्रकार का अवैध कार्य करना पूरी तरह से मना है. प्राकृतिक स्थल को नुकसान पहुँचाने या नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गोरम घाट
GORAM GHAT

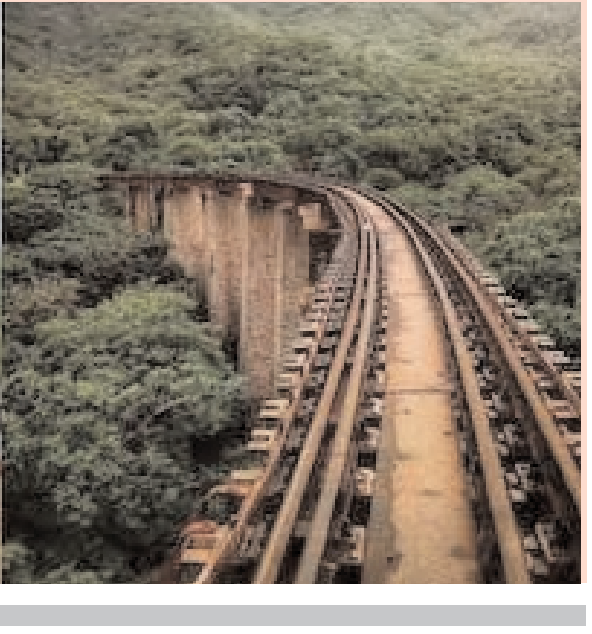

'मिर्जापुर: द फिल्म' को लेकर श्वेता त्रिपाठी बोलीं-

'गोलू गुप्ता का सफर मेरे करियर का सबसे खास अनुभव'

MIRZAPUR
THE FILM

> किसी किरदार का लोगों के जीवन से जुड़ जाना किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।

मुंबई । लंबे समय से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही 'मिर्जापुर' फ्रेंचाइजी अब ओटीटी की दुनिया से निकलकर बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। 'मिर्जापुर : द फिल्म' में एक बार फिर अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी अपने लोकप्रिय किरदार गोलू गुप्ता के रूप में नजर आएंगी। फिल्म की रिलीज से पहले अभिनेत्री ने अपने किरदार की यात्रा, फ्रेंचाइजी से जुड़े अनुभव और दर्शकों के प्यार को लेकर कई बातें साझा की।

उन्होंने बताया कि गोलू का किरदार समय के साथ काफी बदल गया है और एक ऐसी लड़की से एक मजबूत महिला तक का सफर तय कर चुका है, जो सही और गलत की समझ से आगे बढ़ते हुए ताकत, दर्द, बदले और महत्वाकांक्षा जैसी भावनाओं से गुजरती है।

श्वेता त्रिपाठी ने कहा, ' 'जब हमने करीब आठ साल पहले मिर्जापुर की शूटिंग शुरू की थी, तब हममें से किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर इतना लंबा और खास होगा। एक कलाकार के तौर पर आप हमेशा चाहते हैं कि आपका काम लोगों तक पहुंचे, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जब कोई शो लोगों की बातचीत, मीम्स, सेलिब्रेशन और उनकी भाषा का हिस्सा बन जाए। मिर्जापुर ने यह कर दिखाया।''

उन्होंने कहा, ' 'इस फ्रेंचाइजी ने कलाकारों को ऐसी पहचान दी, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दर्शकों ने सिर्फ कहानी को पसंद नहीं किया, बल्कि इसके किरदारों से गहरा जुड़ाव महसूस किया। लोग मुझे आज भी मेरे असली नाम से ज्यादा गोलू दीदी के नाम से पहचानते हैं।''

फिल्म के रूप में 'मिर्जापुर' के विस्तार को लेकर श्वेता ने कहा, ' 'यह सिर्फ एक सीरीज को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह उन दर्शकों के प्यार का नतीजा है, जिन्होंने कई सालों तक इस कहानी और किरदारों को अपना माना। हर सीजन के बाद लोग और कहानी देखना चाहते थे, किरदारों पर चर्चा करते थे और अपनी-अपनी थ्योरी बनाते थे। कई मायनों में यह फिल्म जितनी हमारी है, उतनी ही दर्शकों की भी है।''

श्वेता त्रिपाठी ने अपने किरदार गोलू गुप्ता के बदलाव को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, ' 'गोलू का सफर बेहद भावनात्मक रहा है। शुरुआत में गोलू एक ऐसी लड़की थी, जो सही और गलत की अपनी समझ के साथ आगे बढ़ती थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे धीरे-धीरे बदल दिया। उसने अपने सफर में कई दर्द झेले, बदले की भावना से गुजरी और ताकत के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश की।''

श्वेता ने कहा, ' 'मेरे लिए इस किरदार को निभाना इसलिए भी खास रहा क्योंकि मैंने लंबे समय तक गोलू के हर बदलाव को महसूस किया। मैंने उसे कई सालों तक जिया है। वह एक ऐसी युवा महिला थी, जो सही काम करने में विश्वास रखती थी और धीरे-धीरे ऐसी इंसान बनी, जो ताकत, दुख, बदले और महत्वाकांक्षा के बीच खुद को संभाल रही थी।''

उन्होंने कहा, ' 'किसी किरदार का लोगों के जीवन से जुड़ जाना किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। गोलू गुप्ता का किरदार मेरे करियर के सबसे यादगार किरदारों में से एक रहेगा।

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर अभिनेता रहमान की सरकार से अपील, बोले- 'छात्र हमारे दुश्मन नहीं, भारत का भविष्य हैं'

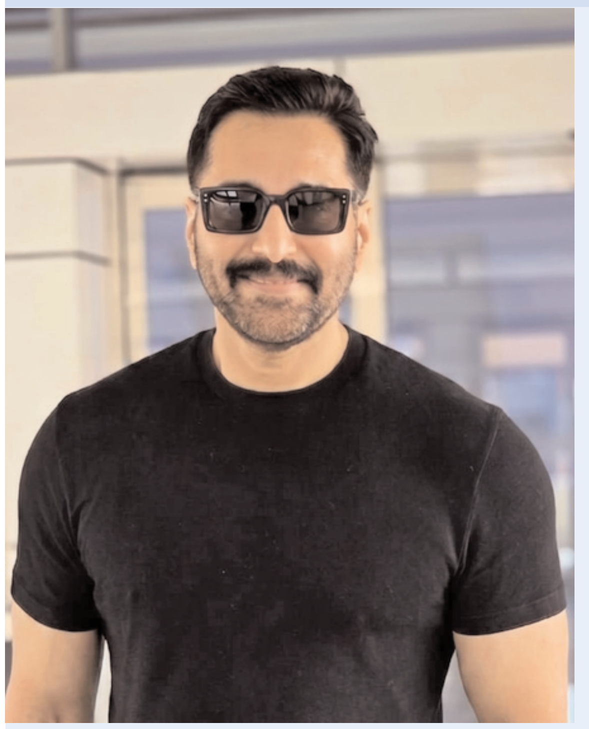

विश्व केसरी

मुंबई । दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन और उस दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है। इस मुद्दे पर अब कई जानी-मानी हस्तियां भी खुलकर अपनी राय रख रही हैं। फिल्मी दुनिया से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में तमिल और मलयालम सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता रहमान ने छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्र देश के दुश्मन नहीं, बल्कि भारत का भविष्य हैं और उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

रहमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, ' 'जब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब मुझे पूरा भरोसा था कि सरकार आगे आएगी, छात्रों की बात सुनेगी और उनकी चिंताओं का समाधान निकालेगी। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, हालात को इस तरह बिगड़ते देखना बेहद तकलीफदेह रहा। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखकर मेरा दिल टूट गया।''

रहमान ने सरकार से सवाल करते हुए कहा, ' 'आखिर क्यों? क्या यह वास्तव में जरूरी था? मैं जानता हूं कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है या मेरी मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस बार मैं किसी अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक चिंतित नागरिक के तौर पर अपनी बात कह रहा हूं।

अपने पोस्ट में रहमान ने सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील भी की। उन्होंने लिखा, ' 'कृपया टकराव की जगह दया और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दीजिए। देर होने से पहले छात्रों की बात सुनिए। हमारे छात्र हमारे दुश्मन नहीं हैं, वे भारत का भविष्य हैं। वे मेरे बच्चों जैसे हैं, वे हम सभी के बच्चे हैं।

रहमान की पोस्ट पर अभिनेत्री रेवती आशा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, ' 'सवाल पूछे जाने चाहिए।

इसके अलावा रेवती ने भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, 'छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, ताकि बच्चों और देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। छात्र मारपीट झेलने के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई युवा अपने भविष्य को लेकर रो रहे है।

'किंग' में शाहरुख के सामने डायलॉग भूल गए थे राघव जुयाल, बोले- सामने आए तो याद आ गया बचपन

मुंबई। अभिनेता राघव जुयाल बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। अभिनेता ने आईएएनएस से हालिया बातचीत में फिल्म में शाहरुख खान के साथ स्क्रीन साझा करने के अनुभव को अपने जीवन का 'सपना सच होने' जैसा बताया।

राघव ने कहा कि शाहरुख खान के साथ पहला सीन करते समय वह काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा, 'जब शाहरुख ने शूटिंग के दौरान पहली बार अपना डायलॉग बोला, तो मैं कुछ देर के लिए अपनी लाइन ही भूल गया था, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं सिंगल-स्क्रीन थिएटर में शाहरुख की फिल्में 5-6 बार देखा करता था।

उन्होंने आगे कहा, 'यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल सपने जैसा था, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस समय मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं शाहरुख खान को कैसे जवाब दूं। फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि मुझे अपना काम अच्छी तरह करना है। सच कहूं तो यह अनुभव बेहद खास, अलग और किसी सपने के सच होने जैसा था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राघव जुयाल एक्शन थ्रिलर 'किंग' में प्रमुख खलनायकों में से एक की भूमिका निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह जैकी श्रॉफ के किरदार के बेटे के रूप में नजर आएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि उनका किरदार शाहरुख खान के किरदार के यंग वर्जन से टकराता है और कहानी में अहम भूमिका निभाता है।

'भाई तेरा सुपरस्टार' का 'आंखों से तूने 2.0' गाना रिलीज, पुराने सिग्नेचर डांस मूव्स में नजर आए राघव जुयाल

विश्व केसरी

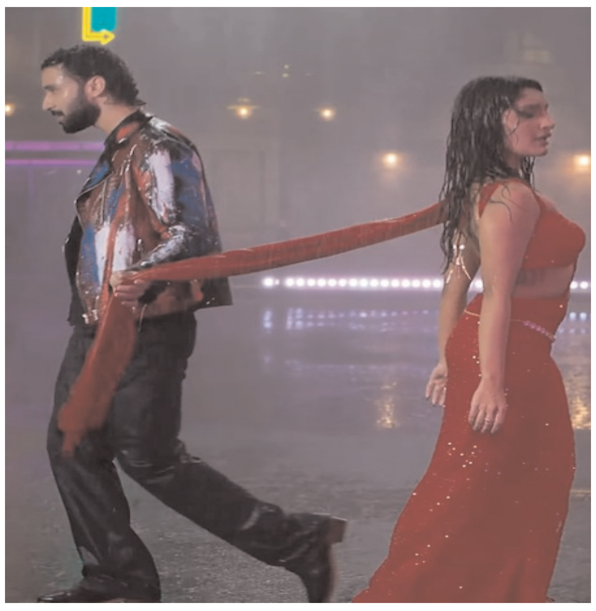

मुंबई । अभिनेता राघव जुयाल स्टारर फिल्म 'भाई तेरा सुपस्टार' का नया गाना 'आंखों से तूने 2.0' बुधवार को मेकर्स द्वारा रिलीज कर दिया गया है। गाने में अभिनेता और निहारिका का खास अंदाज देखने को मिल रहा है, जिसे दर्शक काफी पसंद करते रहे हैं।

अभिनेता राघव जुयाल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर गाने का क्लिप शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'अब जब आंखें ही सब कुछ कहने लगी हैं, तो दिल का धड़कना तो तय है।'आंखों से तूने 2.0' गाना अब रिलीज हो चुका है।'

इस गाने में राघव अपने सिग्नेचर डांस मूव्स के साथ-साथ एक रोमांटिक और स्टाइलिश अवतार में दिखाई दे रहे हैं। उनका यह नया अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। वहीं, निहारिका भी राघव की बीट से बीट मैच करती नजर आ रही हैं।

हालांकि, पुराने मूव्स की वापसी दर्शकों को काफी भा रही है। यह रोमांटिक ट्रैक 90 के दशक के मशहूर क्लासिक गाने का रीमेक है और इसे कुमार शानू और अलका याग्निक जैसे दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज से सजाया था।

इस रीक्रिएटेड गाने को कुमार शानू, अलका याग्निक, देव नेगी और पलक मुच्छल ने अपनी आवाज दी है, जबकि मोहसीन शेख ने इसके गीत को लिखा और लिजो जोर्ज ने इसका संगीत तैयार किया है। वहीं, तुषार कालिया ने गाने को कोरियोग्राफ किया है।

'भाई तेरा स्टार है' में राघव जुयाल लीड एक्टर (अजय सिंह) की भूमिका में हैं, जो लंदन में रहने वाले ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका सपना बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना है। फिल्म का निर्देशन विवेक बी. अग्रवाल ने किया है। राघव जुयाल के अलावा, फिल्म में संजय कपूर, बरखा सिंह, और निहारिका एनएम मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर कुछ समय पहले रिलीज कर दिया गया है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। हिंदी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

क्या भारत में लागू हो सकता है 4-डे वर्क वीक? अभिनेता विक्रांत मैसी ने दिया जवाब

मुंबई। दुनियाभर में '4-डे वर्क वीक' (हफ्ते में चार दिन काम) और वर्क-लाइफ बैलेंस पर बहस तेज हो चुकी है। जहां कई पश्चिमी देश इसे अपना रहे हैं, वहीं भारत में ऐसा होता देखना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर अभिनेता विक्रांत मैसी ने बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी पहलू सामने रखा है।

मनोरंजन जगत की दुनिया सभी को बाहर से चकाचौंध भरी दिखती है, लेकिन अंदर से यहां काम करने वालों की दिनचर्या उतनी ही कठिन है। बिना तय समय के काम करना और छुट्टियों की कमी हमेशा चर्चा का विषय रहता है।

अभिनेता विक्रांत मैसी ने बताया कि चार दिन का वर्क वीक दूसरे देशों में काम कर सकता है, लेकिन भारत में अभी यह मुमकिन नहीं है क्योंकि देश को अपनी ग्रोथ जर्नी में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। अभिनेता ने वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' के प्रमोशन के दौरान इस विषय का मुद्दा छेड़ते हुए बताया, 'उत्तरी यूरोप के देशों में जिस तरह की जीवनशैली और काम करने का तरीका अपनाया जाता है, मुझे नहीं लगता है कि वैसा भारत में अभी हो सकता है। क्योंकि हम अभी भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था हैं और हमारा लोकतंत्र अभी काफी युवा है। एक देश के रूप में हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए भी जरूरी है।

अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि अगर भारत आने वाले दशकों में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करता है, तो ये मुमकिन हो सकता है।

'ऑपरेशन सफेद सागर' में अपने किरदार को दीया मिर्जा ने बताया खास, कहा- एयरफोर्स परिवारों की हिम्मत ने दी प्रेरणा

विश्व केसरी

मुंबई । अभिनेत्री दीया मिर्जा जल्द ही एक ऐसी कहानी के साथ आ रही हैं, जो भारतीय वायुसेना के साहस, जज्बे और परिवारों के अनकहे संघर्षों को सामने लाएगी। वह आने वाली वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में कमलप्रीत कौर धनोआ का किरदार निभाती नजर आएंगी। सीरीज के ट्रेलर लॉन्च के दौरान दीया ने अपने किरदार और उससे जुड़ी भावनाओं को लेकर खुलकर बात की।

उन्होंने बताया कि एयरफोर्स अधिकारियों की पत्नियों की मजबूती, धैर्य और उनके अनकहे बलिदानों ने उन्हें इस भूमिका को निभाने के लिए प्रेरित किया।

दीया मिर्जा ने कहा कि कमलप्रीत कौर धनोआ का किरदार इस कहानी में एक मजबूत आधार की तरह है। वह ऐसी महिला हैं, जो उस समय एयरफोर्स अधिकारियों की पत्नियों का हौसला बनाए रखने का काम करती हैं, जब उनके पति देश की सेवा के लिए मिशन पर होते हैं।

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए दीया मिर्जा ने कहा, ' 'मेरा किरदार कहानी में एक एंकर की तरह है। वह ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने महिलाओं को एक साथ रखा और उन्हें एक ताकत के रूप में जोड़ा। जब उनके पति मिशन पर थे, तब उनके लिए और बाकी महिलाओं के लिए उस परिस्थिति को जीना क्या मायने रखता था, यह कहानी का अहम हिस्सा है।''

दीया ने बताया, 'एयरफोर्स परिवारों की जिंदगी को समझना आसान नहीं है। जो महिलाएं एयरफोर्स में शादी करके आती हैं, उन्हें भी शुरुआत में यह पूरी तरह नहीं पता होता कि आने वाला जीवन कैसा होगा। भले ही वे कई कहानियां सुनती हैं, लेकिन असली परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करना मुश्किल होता है।'

दीया मिर्जा ने कहा, 'इस किरदार से मुझे निजी जिंदगी में भी काफी सीख मिली। एक पत्नी, महिला और मां के रूप में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एयरफोर्स परिवारों की महिलाएं कितनी मजबूत होती हैं। इस कहानी से जुड़ी सबसे बड़ी सीख यह रही कि एयरफोर्स परिवार की पत्नियां अपने पति को हर दिन मुस्कुराकर विदा करती हैं, भले ही पिछली रात उनके बीच कोई बहस ही क्यों न हुई हो। यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, असल जिंदगी में उतनी ही भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण है।'

उन्होंने कहा, ' 'यह एक बहुत मजबूत भावना है। यह सोचकर डर भी लगता है, लेकिन यह उनकी जिंदगी की सच्चाई है।

आसियान के साथ साझेदारी मजबूत करेगा क्वाड, मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत पर बनी सहमति

विश्व केसरी

नई दिल्ली/मनीला। आसियान की बैठक से इतर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने एक अहम बैठक की। इसके बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में सबसे ज्यादा जोर मुक्त एवं खुले इंडो-पैसेफिक पर दिया गया। आसियान के साथ सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

यह संयुक्त बयान भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से जारी किया गया। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त बयान को साझा किया है। इसके अनुसार, आसियान के व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने बुधवार को मनीला में बैठक कर मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मजबूत बनाने के साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।

बयान में कहा गया कि क्वाड देशों की क्षेत्र की सफलता में गहरी भागीदारी है और वे आसियान तथा उसके सदस्य देशों के साथ सहयोग को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्वाड नेताओं ने क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा की। उन्होंने समुद्री एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता एवं आपदा प्रतिक्रिया जैसे साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम से आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) के व्यावहारिक क्रियान्वयन को मजबूत करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि चारों देश इस विश्वास में एकजुट हैं कि हिंद-प्रशांत के समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता ही पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला है।

विदेश मंत्री ने एक्स पर भी इस बैठक में साझा किए गए विचारों का उल्लेख किया। अपने पोस्ट में जयशंकर ने कहा, 'मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होकर खुशी हुई।' उन्होंने आगे लिखा, 'बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। साथ ही, नई दिल्ली में हाल ही में हुई क्वाड बैठक के निर्णयों और उनके क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। हमने आसियान की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करते हुए मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।'

पाकिस्तान के पंजाब में बारिश का कहर : 8 की मौत और 14 घायल, कई इलाके जलमग्न

विश्व केसरी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में बारिश कई इलाकों पर कहर बन कर टूटी है। खासकर पंजाब प्रांत गुजरांवाला, नारोवाल, पाकपत्तन और लाहौर शहरों में भारी बरसात ने तबाही मचा दी है। अलग-अलग हादसों में करीब 8 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गुजरांवाला शहर में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। वहीं, गुजरात में जीटी रोड बाईपास पर बारिश के कारण फिसलने के बाद एक ट्रेलर खाई में गिर गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, राहत एवं बचाव अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं में मौत का कारण मकान की छत और दीवार गिरने से लगी चोट, तालाब में डूबने या फिर करंट लगना रहा। पाकपत्तन में बारिश के दौरान एक मकान की छत गिरने से दो नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां घायल हो गईं। वहीं, लाहौर के गुलशन-ए-रावी इलाके में एक फैक्ट्री की छत गिरने से चार मजदूर घायल हो गए।

गुजरात और गुजरांवाला शहरों में करीब 10 घंटे तक हुई भारी बारिश के बाद मुख्य सड़कें और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। बारिश के कारण व्यावसायिक गतिविधियां और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। डॉन के मुताबिक, गुजरांवाला शहर पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा, जहां भारी बारिश के साथ-साथ एमिनाबाद और गखड़ मंडी के बीच मेट्रो बस मार्ग निर्माण के लिए जीटी रोड पर चल रहे खुदाई कार्य ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर और अन्य जिलों में मूसलाधार बारिश तथा अचानक आई बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई थी। द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, खैबर, मर्दान और बाजौर में मौतों की सूचना मिली, जबकि अचानक आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से मानसेहरा, एबटाबाद, चित्राल, शांगला और अन्य जिलों में सड़कें, पुल, मकान, दुकानें, मछली फार्म, बागान, फसलें और सार्वजनिक ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए।

संक्षिप्त खबर

अमेरिका ने ईरान युद्ध का खर्च 37.5 अरब डॉलर बताया

Hon. Peter B. Hegseth

विश्व केसरी

वॉशिंगटन। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सीनेटरों को बताया कि ईरान के साथ जारी युद्ध में अब तक अनुमानित 37.5 अरब डॉलर का खर्च आया है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में फिर से शुरू हुई लड़ाई के बीच लगभग 88 अरब डॉलर की आपातकालीन फंडिंग की मांग की है। हेगसेथ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अतिरिक्त फंडिंग की मांग पर सीनेट की एप्रोप्रिएशन कमेटी की सुनवाई के दौरान यह आंकड़ा बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन 87.6 अरब डॉलर की मांग कर रहा है, जिसमें सेना के लिए लगभग 67 अरब डॉलर शामिल हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड डर्बिन के सवालों के जवाब में हेगसेथ ने कहा, 'आज हमारे पास जो अनुमान है, वह 37.5 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि इस अनुमान में अब तक हुए कुछ खर्च और 30 सितंबर तक सेना के वेतन, ऑपरेशन और रखरखाव के संभावित खर्च शामिल हैं। इस मांग से सेना की तैयारी के लिए 21 अरब डॉलर मिलेंगे, जिसमें वेतन, उपकरण बदलना, आगे तैनात सेना, ईंधन और नेशनल गार्ड का सहयोग शामिल है। इसके अलावा, 46 अरब डॉलर से गोला-बारूद का उत्पादन बढ़ेगा और हाइपरसोनिक हथियारों, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट और अन्य क्षमताओं में निवेश में तेजी आएगी।

हूती धमकियों पर कुवैत ने सऊदी अरब का किया समर्थन, समुद्री सुरक्षा पर दिया जोर

विश्व केसरी

कुवैत सिटी। कुवैत ने यमन के हूती समूह की ओर से सऊदी अरब से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की धमकियों की निंदा की और रियाद (सऊदी अरब) को अपना पूरा समर्थन दोहराया। कुवैत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री रास्तों से आने-जाने की आजादी और सुरक्षा को बनाए रखना जरूरी है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में हूती समूह के सऊदी अरब के खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। मंत्रालय ने समुद्री यातायात की 'आजादी और सुरक्षा' को खतरा पहुंचाने वाली धमकियों की भी आलोचना की। कुवैत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों को लागू करवाने में मदद करे। इनमें यमन से जुड़ा प्रस्ताव 2216 और लाल सागर में समुद्री आवाजाही की सुरक्षा से जुड़ा प्रस्ताव 2722 शामिल हैं। बयान में कुवैत ने फिर से कहा कि वह सऊदी अरब के साथ पूरी तरह खड़ा है और अपनी सुरक्षा व संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की ओर से उठाए गए कदमों का समर्थन करता है। यह बयान हूती समूह की ओर से सऊदी अरब से जुड़े जहाजों पर समुद्री प्रतिबंध लगाने की घोषणा के एक दिन बाद आया। हूती समूह ने यह कदम पिछले हफ्ते सना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी अरब की ओर से की गई बमबारी के आरोप के बाद उठाया था।

न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का यू-टर्न, बोले- नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं

विश्व केसरी

वॉशिंगटन। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने कहा कि सिटी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के तहत इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। कानूनी समीक्षा में यह निष्कर्ष निकलने के बाद कि उनके प्रशासन के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अपने चुनावी वादे से पीछे हटते हुए यह बात कही।

हालांकि, ममदानी ने नेतन्याहू को 'युद्ध अपराधी' कहा और ट्रम्प प्रशासन से आग्रह किया कि वे सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क आने पर उन्हें गिरफ्तार करें। ममदानी ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'मेरे प्रशासन ने लागू कानून के तहत उपलब्ध हर रास्ते की समीक्षा की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू यहां आते हैं तो क्या न्यूयॉर्क शहर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ़्तारी वारंट को लागू कर सकता है।' उन्होंने कहा, 'यह स्पष्ट है कि हमारे पास इस वारंट को लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है।' ममदानी ने कहा कि संघीय सरकार के पास ऐसा अधिकार है और उन्होंने वॉशिंगटन से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल होने और उसके वारंट को लागू करने का आह्वान किया। अमेरिका इस कोर्ट का सदस्य नहीं है।

मेयर की यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई कि नेतन्याहू को उनकी अमेरिकी यात्रा के दौरान हिरासत में नहीं लिया जाएगा। ट्रम्प ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।' अपने मेयर पद के चुनाव अभियान के दौरान, ममदानी ने बार-बार कहा था कि जब इजराइली नेता न्यूयॉर्क आएंगे तो वे नेतन्याहू की गिरफ्तारी का आदेश देंगे। उन्होंने हाल ही में 'द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन' को बताया था कि उनका प्रशासन वारंट को लागू करने के बारे में शहर के कानून विभाग के साथ सक्रिय बातचीत कर रहा था। कानूनी निष्कर्ष के बावजूद ममदानी ने नेतन्याहू की आलोचना जारी रखी। उन्होंने कहा, 'बेंजामिन नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी हैं।

'विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन- 2026' संपन्न

विश्व केसरी

बीजिंग। 'विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन- 2026' का समापन 20 जुलाई को शांगहाई वर्ल्ड एक्सपो सेंटर में हुआ, जिसमें 4 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आंकड़ों के अनुसार, सम्मेलन में 177 प्रमुख वैश्विक खरीद प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, और अनुमानित खरीद राशि लगभग 20.36 अरब युआन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। समापन समारोह में, उद्योग जगत के पेशेवरों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए और अगले सम्मेलन के लिए अपनी उच्च उम्मीदें व्यक्त कीं। शांगहाई से कई महत्वपूर्ण एआई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें एआई अवसंरचना, बुद्धिमान एजेंट अनुप्रयोग, अंतर्निहित बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों की 32 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका कुल निवेश 40.9 अरब युआन से अधिक है।

प्रतिभागियों का मानना था कि सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार, औद्योगिक विकास और वैश्विक शासन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो एआई के सकारात्मक और नैतिक विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक एआई विकास और शासन में नई गति प्रदान करने में चीन की जिम्मेदारी को पूरी तरह से प्रदर्शित करती हैं।

बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप बढ़ा, 'वैक्सीनेशन गैप' बड़ी वजह

विश्व केसरी

ढाका। बांग्लादेश में खसरे ने कई मासूमों की जान ले ली है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, देश में हर दिन औसतन करीब 4 बच्चों की मौत हो रही है और 800 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस बीच, सरकार और आम लोगों का ध्यान इस स्वास्थ्य संकट से कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में खसरे के लगातार बढ़ते प्रकोप का अहम कारण 'वैक्सीनेशन गैप' को बताया जा रहा है। सरकार के इस दावे के बावजूद कि उसने आपातकालीन खसरा टीकाकरण अभियान का लक्ष्य पार कर लिया है, अस्पतालों में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है। इससे टीकाकरण कवरेज में मौजूद कमियों का पता चलता है। जुलाई के पहले तीन हफ्तों में खसरे का प्रकोप गंभीर बना रहा। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान हर दिन औसतन 1,005 संदिग्ध और लैब टेस्ट से कन्फर्म किए गए खसरे के मामले सामने आए, 821 अस्पताल में भर्ती किए गए और रोजाना करीब 4 बच्चों की मौत दर्ज की गई। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार 'द डेली स्टार' ने खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सत्यापन समिति के अध्यक्ष महमूदुर रहमान के हवाले से कहा, 'स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन टीकाकरण अभियान के दो महीने बाद भी यह अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

ऐसा लगता है कि अधिकारी इस

चीन ने फिलीपींस के सामने गंभीरता से मामला उठाया

विश्व केसरी

बीजिंग। चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागर मामला विभाग के अधिकारी ने मंगलवार को चीन स्थित फिलीपींस के राजदूत को तलब किया और गंभीरता से मामला उठाया।

चीनी अधिकारी ने कहा कि फिलीपींस ने रनआईच्याओ रीफ पर उत्तेजक कार्रवाई कर चीनी तटरक्षक बल के कानून प्रवर्तन कर्मियों पर हमला किया। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। रनआईच्याओ रीफ चीन के नानशा द्वीप समूह का एक हिस्सा है और चीन की प्रादेशिक भूमि का एक भाग है। रनआईच्याओ रीफ के आसपास समुद्री क्षेत्रों में चीनी तटरक्षक बल की कानून प्रवर्तन कार्रवाई उचित और कानूनी है। फिलीपींस के रनआईच्याओ रीफ पर अवैध रूप से बैठे युद्धपोत द्वारा छोड़ी दो रबर वाली नावों ने खतरनाक तरीके से चीनी तटरक्षक जहाज के पास जाकर टक्कर मारी। फिलीपींस के लोगों ने जानबूझकर चीनी कानून प्रवर्तन कर्मियों को परेशान किया और उन पर हमला किया। इससे चीनी कर्मियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी। फिलीपींस की कार्रवाई बहुत खतरनाक है। चीनी अधिकारी ने कहा कि फिलीपींस ने सबसे पहले उत्तेजक कार्रवाई की। इसके बजाय तथ्यों को तोड़कर और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करके चीन पर आरोप लगाया। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चीन फिलीपींस से तुरंत उत्तेजक कार्रवाई और बुरा प्रचार बंद करने की मांग करता है। चीन दृढ़ता से अपनी प्रभुसत्ता और समुद्री अधिकार व हित की रक्षा करने के लिए कदम उठाएगा। उधर, चीनी तटरक्षक बल के प्रवक्ता च्यांग ल्वे ने बताया कि मंगलवार की सुबह, मानवीय दृष्टिकोण से चीन ने फिलीपींस को 'रन-आए च्याओ' के जल क्षेत्र में गैर-कानूनी रूप से फंसे जहाज 57 से घायलों को छोटी नाव के जरिए फिलीपींस कोस्ट गार्ड के जहाज 9702 पर ले जाने की इजाजत दी।

सीजीटीएन सर्वे : जब मशीनें सोचना शुरू कर देंगी, तो इंसान को किन सवालों के जवाब देने होंगे?

विश्व केसरी

बीजिंग। इतिहास में, हर तकनीकी क्रांति ने मानवीय क्षमताओं के प्रदर्शन और मानवता की परिभाषा में एक नया आयाम जोड़ा है। लेकिन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इससे कहीं अधिक गहरा बदलाव लाती है। यह अब केवल वास्तविकता को दर्ज नहीं करती, बल्कि उसका पूर्वानुमान भी लगाने लगी है।

यह अब केवल दुनिया की मौजूदा स्थिति को ही नहीं दर्शाती, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को सामने आने से पहले ही व्यवस्थित करने लगी है। इस अर्थ में, भविष्यवाणी अब केवल भविष्य के संभावित परिणामों का वर्णन नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति बन गई है जो आने वाले समय को सक्रिय रूप से आकार देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा सबसे गहरा सवाल यह नहीं है कि मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उनके निर्णयों को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त होने लगा है। यह अधिकार कौन प्रदान करता है? कौन इसकी जवाबदेही तय करता है? और अंततः, यह मानवता के लिए किस प्रकार का भविष्य निर्मित करेगा? सीजीटीएन के एक वैश्विक ऑनलाइन सर्वेक्षण के मुताबिक 85.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तीव्र विकास वैश्विक सुरक्षा और शासन के लिए नई चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। 92.6 प्रतिशत ने चिंता व्यक्त की कि डीपफेक और एआई द्वारा उत्पन्न गलत सूचनाएं सामाजिक विश्वास की नींव को ही कमजोर कर सकती हैं, जबकि 87.8 प्रतिशत ने आशंका जताई कि तकनीकी बाधाएं और 'डिजिटल दीवारें' वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को खंडित कर सकती हैं।

रिसर्च और डेवलपमेंट की रेस में अमेरिका के बराबर पहुंचा चीन : व्हाइट हाउस रिपोर्ट

THE WHITE HOUSE
250

विश्व केसरी

वॉशिंगटन। व्हाइट हाउस ने विज्ञान नीति पर एक बड़ी रिपोर्ट में कहा है कि रिसर्च पर खर्च के मामले में चीन अमेरिका का बराबरी का कॉम्पिटिटर बन गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बीजिंग की सुनियोजित कोशिशों से अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी में उसकी क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं।

यह आकलन 'साइंस: ए न्यू गोल्डन एज' में किया गया है। इसे व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ने मंगलवार को जारी किया था। यह अमेरिका के सालाना लगभग 200 अरब डॉलर के फेडरल रिसर्च और डेवलपमेंट सिस्टम को फिर से व्यवस्थित करने का एक ब्लूप्रिंट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले बीस सालों में, चीन का रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च, जो पहले अमेरिका के मुकाबले न के बराबर था, कुछ पैमानों के अनुसार 'परचेजिंग-पावर-एडजस्टेड' आधार पर अब अमेरिका के बराबर हो गया है। इसमें इस कॉम्पिटिशन की तुलना कोल्ड वॉर (शीत युद्ध) के दौर से की गई है। रिपोर्ट में अमेरिका, चीन और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ की तुलना करने वाले एक चार्ट में कहा गया है, 'पहली बार, अमेरिका को रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च में 'परचेजिंग पावर पैरिटी' (पीपीपी)-एडजस्टेड आधार पर बराबरी का कॉम्पिटिटर मिला है।' दस्तावेज़ में कहा गया है कि बीजिंग ने वैज्ञानिक रिसर्च क्षमता को अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के केंद्र में रखा है, जिसमें सबसे ऊंचे स्तर पर फैसले लिए जाते हैं और अलग-अलग सेक्टर में रिसर्च की कोशिशों में तालमेल बिठाया जाता है। इसमें कहा गया है, 'समाज के सभी वर्गों को शामिल करने वाले इस नजरिए की वजह से चीन बुनियादी वैज्ञानिक रिसर्च के लिए संसाधन जुटा पाया है, राष्ट्रीय हित की अहम टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ पाया है और अपनी इनोवेशन प्रक्रिया में सुधार कर पाया है।' 'चीन की पहचान ऑटोनॉमस वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (खुद काम करने वाली लैब) में भी एक कॉम्पिटिटर के तौर पर की गई है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स प्रयोगों को डिजाइन करने और उन्हें करने में मदद कर सकते हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट को पहले सीईओ के लिए अभी करना होगा इंतजार, स्क्रीनिंग प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई

विश्व केसरी

नई दिल्ली। राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बुधवार को अयोध्या में एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी, जिसमें राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति और ट्रस्ट में खाली पड़े तीन पदों को भरने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि सीईओ की नियुक्ति पर अंतिम फैसला होने की संभावना कम है, क्योंकि आवेदकों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।

सूत्रों के मुताबिक, सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए बनाई गई तीन सदस्यों वाली एक्सपर्ट कमेटी को बहुत सारे आवेदन मिले हैं, जिससे तय समय में स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरा करना मुश्किल हो गया है। इस वजह से कमेटी के ट्रस्ट की बैठक से पहले तीन उम्मीदवारों की फाइनल शॉर्टलिस्ट सौंपने की संभावना कम है, जिससे मंदिर के पहले प्रोफेशनल सीईओ के चयन में देरी होगी। सीईओ का पद बनाने का फैसला ट्रस्ट की 6 जुलाई की बैठक में लिया गया था, जो मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों के बाद हुआ था। तब ट्रस्ट ने मंदिर के मैनेजमेंट को मजबूत करने, फाइनेंशियल पारदर्शिता लाने, सुरक्षा इंतजाम बेहतर करने और भक्तों के लिए सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लाने का फैसला किया था। नियुक्ति के बाद सीईओ मंदिर के रोजाना के कामकाज, मैनेजमेंट के फैसलों को लागू करने और स्टाफ की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। ट्रस्ट की मंजूरी से सीईओ को मंदिर के कामकाज के लिए सेक्रेटरी और दूसरे जरूरी कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार भी होगा।

सीईओ की नियुक्ति के अलावा ट्रस्ट ने तीन खाली पदों को भरने पर भी चर्चा है। एक पद अयोध्या के शाही परिवार के पूर्व प्रमुख और ट्रस्टी बिमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद खाली हुआ था, जबकि बाकी दो पद पूर्व जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद खाली हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, कृष्ण मोहन ट्रस्ट के स्थायी महासचिव बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं।

भारत अपने मूल्यों व साहस से दुनिया का विश्वास जीतता है : राजनाथ सिंह

विश्व केसरी

नई दिल्ली। कुछ राष्ट्र अपनी बात शब्दों से कहते हैं। भारत अपने मूल्यों, अपने आचरण और अपने साहस से दुनिया का विश्वास जीतता है। यह बात बुधवार को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कही। वह, त्रि-सेवा विश्व परिक्रमा नौकायन अभियान के पूरा होने पर सैन्यकर्मियों के बीच बोल रहे थे। विश्व परिक्रमा नौकायन के इस अभियान को पूरी तरह से तीनों सेनाओं की महिला कर्मियों ने अंजाम दिया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना की महिला अधिकारियों ने एक ध्वज के तले यह अभियान पूरा किया है।

यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व संयुक्त ऑपरेशन, इंटेग्रिटीड कमांड और मल्टी डोमेन वॉरफेयर की बात कर रहा है, तब आईएएसवी त्रिवेणी ने समुद्र के बीच उस संयुक्ता को जीकर दिखाया है। उन्होंने कहा कि जहाँ समन्वय होता है, वहाँ सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाती है। और जहां तीनों सेनाएं साथ चलती हैं, वहां विजय स्वयं रास्ता बना लेती है। रक्षा मंत्री ने कहा, 'आईएएसवी त्रिवेणी आत्मनिर्भर भारत की भी एक जीवंत पहचान है। देश में डिजाइन और निर्मित इस पोत ने पूरी दुनिया के समुद्रों में भारत की तकनीकी क्षमता, हमारे नवाचार और हमारे आत्मविश्वास का परिचय दिया है। यह वेसल, भारत की इंजीनियरिंग एक्सेलेंस, स्वदेशी क्षमता और रणनीतिक आत्मविश्वास का चलता-फिरता प्रमाण था। त्रिवेणी ने जितनी समुद्री मील तय की हैं, उतने ही कदम भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ाए हैं।' रक्षा मंत्री ने महिला सैनिकों से कहा कि आप जहां-जहां गईं, वहां आपने केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं पहुंचाया बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी परिचय कराया। विभिन्न देशों के बंदरगाहों पर आपके संवाद, आपके व्यवहार और आपके व्यक्तित्व ने भारत की उस सॉफ्ट पावर को भी मजबूत किया, जिसकी आज पूरी दुनिया प्रशंसा करती है।

संक्षिप्त खबर

पुंछ में भूस्खलन की चपेट में आने से बाच-बाल बचे सांसद मियां अल्ताफ अहमद

विश्व केसरी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मियां अल्ताफ अहमद बुधवार को पुंछ-जम्मू नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से बाल-बाल बच गए। उनके काफिले की एक गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई थी। आईएएनएस से बात करते हुए मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि वह ठीक थे और लैंडस्लाइड पार कर चुके थे, तभी उनके काफिले की एक गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि उस गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। पिछले कुछ दिनों से बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को दूर करने के लिए मियां अल्ताफ राजौरी में कैंप कर रहे हैं। वह लैंडस्लाइड से प्रभावित दूरदराज के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जब वह पुंछ जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों से लौट रहे थे, तो जम्मू-पुंछ नेशनल हाईवे पर उनके काफिले की एक गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई थी लेकिन वे बाल-बाल बच गए। मियां अल्ताफ अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर जानकारी दी थी, पुंछ के बाद राजौरी पहुंचा ताकि इलाके में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण पैदा हुए हालात का जायजा ले सकूं। राजौरी जाते समय एक लैंडस्लाइड हो गया था जिससे सड़क बंद हो गई थी। हालांकि मैं सुरक्षित रूप से राजौरी पहुंचने में कामयाब रहा।

कांग्रेस सांसदों ने सरकार पर कसा तंज, कहा- 'आंदोलन को बलपूर्वक दबाने में जुटी सरकार'

विश्व केसरी

नई दिल्ली। छात्रों से जुड़े मुद्दों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग करने और संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सरकार पर छात्रों के खिलाफ राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लंबे भाषण देने के बजाय तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष को मंत्री का स्पष्टीकरण नहीं बल्कि उनका इस्तीफा चाहिए। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि जब विपक्ष किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह उस पर चर्चा करे। सरकार संवाद करने के बजाय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक दलों की लड़ाई से ऊपर बताते हुए कहा कि यह देश के भविष्य और छात्रों को न्याय दिलाने की लड़ाई है। देश का युवा देख रहा है कि इस मुद्दे पर कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके रास्ते में बाधा बन रहा है। कांग्रेस सांसद जोथिमानि ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है ।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात पर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा- 'हमारी मांगें पूरी करेंगे, तभी हमें बुलाइए'

विश्व केसरी

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। इसी बीच सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हमारा समय कीमती है और हम केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से तभी मुलाकात करेंगे, जब वे हमारी मांगों को पूरा करने के लिए मानेंगे।

नई दिल्ली में आईएएनएस से बातचीत में सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया, 'हमने साफ तौर पर कह दिया है कि हम घर या ऑफिस नहीं आ रहे हैं। पहली मुलाकात में हमें चार घंटे रोके रखा गया था। हमारी तरफ से कहा गया है कि अगर हमारी मांगें पूरी करेंगे, तभी हमें बुलाइए।' सौरव दास ने पीएम आवास के बाहर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनका कर्तव्य प्रदर्शन करना है। उन्होंने जिस तरह से विरोध-प्रदर्शन किया, उससे हम बहुत खुश हैं। विरोध होना चाहिए। हम सभी का एक ही मुद्दा है कि नीट पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, यही हमारी मुख्य मांग है।

प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्रकारों, पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमलों के सवाल पर सौरव दास ने कहा कि 20 जुलाई को सबसे ज्यादा पुलिस की ओर से ही लाठियां चलाई गईं। उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ। जिस तरह दहशतगर्दी की गई, बच्चों के सिर पर चोटें आईं। कुछ लोग सेल्फ डिफेंस में धक्का-मुक्की कर रहे होंगे, लेकिन हम स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसे प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जो हिंसा कर रहे हैं, पुलिस को उन्हें हटाना चाहिए। क्योंकि, हमारे प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं है।' उन्होंने कहा कि मीडिया हमें टारगेट करने के लिए बैठी है। हमारे युवा पढ़े-लिखे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हिंसा हमारे आंदोलन को कमजोर कर सकती है। आम आदमी पार्टी की बी-टीम बताए जाने पर सौरव दास ने कहा, 'हमें तो कुछ लोगों ने आतंकवादी भी कहा है, तो हमें अरेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन, देश के 65 प्रतिशत युवा जानते हैं कि सच क्या है। युवा हमें भरपूर समर्थन दे रहे हैं। यहां लोगों के बिना किसी अपील के खाना-पानी पहुंचाया जा रहा है।' उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'पैसे लेकर जो लोग सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, वे अपना काम करते रहें।

जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस के जवान की 'हार्टअटैक' से मौत की खबर फर्जी निकली, पुलिस ने किया खंडन

विश्व केसरी

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस के 42 वर्षीय जवान सतीश की हार्टअटैक से मौत होने की खबर बुधवार को सोशल मीडिया और इंटरनेट के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गई। हालांकि, जांच के बाद यह दावा पूरी तरह फर्जी और भ्रामक निकला।

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि जंतर-मंतर पर धरने के पास ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी की हार्टअटैक से मौत हो गई। खबर वायरल होने के बाद मामले की विभिन्न स्तरों पर जानकारी जुटाई गई लेकिन कहीं से भी इस घटना की पुष्टि नहीं हुई। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने सभी स्तरों पर जानकारी लेने की कोशिश की लेकिन अब तक ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है।

अधिकारी ने कहा कि फिलहाल हमारे पास ऐसी किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। यदि किसी को पता है कि यह खबर सबसे पहले कहां से फैली, तो इसकी जानकारी दी जाए ताकि संबंधित व्यक्ति या प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा जा सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है और न ही किसी पुलिसकर्मी की हार्टअटैक से मौत की पुष्टि हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इसी दौरान एक अधिकारी ने यह भी पुष्टि की कि ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं संक्षिप्त समय के लिए गोलीबारी हुई थी, जिसका सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। हालांकि, यह जानकारी जंतर-मंतर पर वायरल हो रही मौत की खबर से संबंधित नहीं है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य कर लें।

घर मिला, लेकिन सड़क नहीं! कानपुर देहात की आसरा कॉलोनी में बदहाल जिंदगी

विश्व केसरी

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार की आवास योजनाओं के तहत गरीब परिवारों को पक्का घर तो मिल गया, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उनका जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ है। कानपुर देहात की आसरा आवास कॉलोनी में रहने वाले करीब 400 परिवार जलभराव, टूटी सड़कों, बिजली और पानी की समस्याओं से परेशान हैं। बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत और धरना-प्रदर्शन करने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

कॉलोनी में रहने वाले बुद्ध प्रकाश ने बताया कि वह पिछले एक साल से यहां रह रहे हैं। उनके अनुसार सबसे बड़ी समस्या सड़क और कीचड़ की है। बारिश होते ही पूरी कॉलोनी की सड़कें दलदल में बदल जाती हैं, जिससे बच्चों का स्कूल जाना बेहद कठिन हो जाता है। स्कूल वाहन कॉलोनी के अंदर आने से मना कर देते हैं, इसलिए अभिभावकों को छोटे बच्चों को गोद या कंधे पर बैठाकर मुख्य सड़क तक छोड़ने जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल से निकलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि सरकार को पहले सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करनी चाहिए थीं, उसके बाद ही मकानों का आवंटन करना चाहिए था।

स्थानीय निवासी सुहाना बेगम ने बताया कि वह पिछले चार वर्षों से इस कॉलोनी में रह रही हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी भर जाता है। सड़कें कच्ची हैं और नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाते समय फिसलकर गिर जाते हैं और कई बार घायल भी हो चुके हैं।

भोपाल में भाजपा नेता काले कपड़े पहनकर कांग्रेस दफ्तर घेरने सड़क पर उतरे

विश्व केसरी

भोपाल। दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देने के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। साथ ही, वे कांग्रेस दफ्तर घेरने सड़कों पर उतरे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता राजधानी के रेड क्रॉस चौराहे पर जमा हुए। प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम बड़े नेता काले कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के करीब दिए गए धरने का विरोध किया। यहां भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को संविधान विरोधी बताया, साथ ही कार्यकर्ताओं के हाथ में नारे लिखी हुई तख्तियां थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार संविधान की हत्या कर रहे हैं। उन्हें चुनाव में हार मिलती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पिछले दरवाजे से इस तरह की अराजकता फैलाने का काम करती है। भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की संविधान विरोधी इस गतिविधि का विरोध करते हैं। कांग्रेस जो चुनाव में सफल नहीं होती वह कहीं न कहीं लोकतंत्र को दबाने का काम करती है और अराजकता के रास्ते को अपनाती है। खंडेलवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस के इस कृत्य का भाजपा विरोध करती है, इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राहुल गांधी द्वारा विदेशी मंचों पर दिए जाने वाले बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता रेड क्रॉस चौराहे से कांग्रेस दफ्तर की ओर आगे बढ़े, लेकिन पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग के चलते आगे नहीं जा सके।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग आतंकी हमले की निंदा की

विश्व केसरी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बुधवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अनंतनाग कस्बे में हुए आतंकी हमले की जानकारी दी। इस हमले में एक स्थानीय पुलिसकर्मी शहीद हो गया। डीजीपी प्रभात, विशेष डीजीपी जावेद मुजतबा गिलानी और आईजीपी कश्मीर वीके बर्डी हमलावरों का पता लगाने के लिए शुरू किए गए तलाशी अभियान का निरीक्षण करने अनंतनाग कस्बे पहुंचे। उपराज्यपाल सिन्हा ने अनंतनाग में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने हमले के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए डीजीपी नलिन प्रभात से बात की। उन्होंने कहा कि मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस जघन्य कृत्य को बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाने वाले हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।

शेलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस 'मालवन', दुश्मन की पनडुब्बी की टोह लेगा

विश्व केसरी

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना में एक नया योद्धा 'आईएनएस मालवन' शामिल हुआ है। यह एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित माहे श्रेणी का 'एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट' है। यह उथले जल में अपने मिशनों को अंजाम देने में पूरी तरह से सक्षम है। आईएनएस मालवन को बुधवार को करवार में औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया।

नौसेना के अनुसार, आईएनएस मालवन बड़े युद्धपोतों, पनडुब्बियों और नौसैनिक विमानन संसाधनों के साथ समन्वित रूप से संचालन करने में सक्षम है। इसके शामिल होने से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता और समुद्री सुरक्षा तंत्र को नई मजबूती मिलेगी। नौसेना का कहना है कि यह युद्धपोत भारत के समुद्री हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए हर समय और हर परिस्थिति में तत्पर रहेगा। युद्धपोत के प्रतीक चिह्न में 'बाघ नख' को दर्शाया गया है। यह प्रतीक चिह्न साहस, युद्ध कौशल, फुर्ती और दुश्मन पर तेज एवं सटीक प्रहार की क्षमता का प्रतीक है। इसके चारों ओर बनी समुद्री लहरें भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के प्रति नौसेना की सतत सतर्कता और प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। पोत का ध्येय वाक्य 'साइलेंट क्लॉज' है, जो इसकी गुप्त, घातक और त्वरित आक्रमण क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। इस युद्धपोत का निर्माण 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री और प्रणालियों के साथ किया गया है। यह माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धपोत है, जिसके शामिल होने से नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। आईएनएस मालवन के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने की। इस अवसर पर पश्चिमी नौसैनिक कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि, नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व सैनिक और अन्य विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। आईएनएस मालवन का नाम भारतीय नौसेना के पूर्व इनशोर माइंसवीपर पोत मालवन के नाम पर रखा गया है, जिसे वर्ष 2003 में 19 वर्षों की गौरवशाली सेवा के बाद सेवामुक्त किया गया था। यह परियोजना भारत के बढ़ते नौसैनिक डिजाइन, उपकरण निर्माण और प्रणाली एकीकरण तंत्र को मजबूती प्रदान करती है। 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित होने के कारण यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत अभियान का महत्वपूर्ण उदाहरण भी माना जा रहा है।

विक्रम-1 मिशन से निजी स्पेस कंपनियों को मिली मजबूती, 2030 तक वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ के ऑर्बिट तक पहुंचने से भारत के स्पेस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया है; यह सरकारी एकाधिकार से हटकर ‘मल्टी-एक्टर स्पेस इकोसिस्टम’ की ओर बढ़ने का संकेत है।

'इंडिया नैरेटिव' की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘भारत अब सिर्फ इसरो का कम लागत वाला विस्तार नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा देश बन गया है जो कई तरह के खिलाड़ियों वाला स्पेस इकोसिस्टम बना रहा है। इसके पास अपने रॉकेट, सैटेलाइट और भविष्य में अपने क्रू वाले मिशन और स्पेस स्टेशन भी होंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विक्रम-1 उस कहानी को आगे बढ़ाता है जो चंद्रयान-3 की लैंडिंग और आदित्य-एल1 के सोलर मिशन से शुरू हुई थी। इसमें यह भी बताया गया है कि 2020 के आसपास शुरू हुए सुधारों और इन-स्पेस के गठन ने इस मिशन की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई।

रिपोर्ट के अनुसार, इन-स्पेस ने स्काईरूट को अपना हार्डवेयर टेस्ट करने और श्रीहरिकोटा में इसरो की अपनी रेंज से लॉन्च करने में मदद की।

इन-स्पेस प्राइवेट लॉन्चर बनाने वालों, सैटेलाइट बनाने वालों और डाउनस्ट्रीम सर्विस प्रोवाइडर्स को एक ही नेशनल इकोसिस्टम में जोड़ता है, न कि उन्हें अलग-अलग और स्वतंत्र क्षमताएं विकसित करने के लिए छोड़ देता है।

हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने इस मिशन में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें रॉकेट के लिए ऑल-कार्बन कम्पोजिट मोटर केसिंग, हाई-परफॉर्मेंस सॉलिड मोटर्स और 3डी-प्रिंटेड प्रोपल्शन कंपोनेंट्स शामिल थे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल तक ये मैन्युफैक्चरिंग तकनीकें सिर्फ इसरो और दुनिया की कुछ बड़ी एयरोस्पेस कंपनियों के पास ही थीं।

रिपोर्ट में कहा गया, ‘इसमें भारत की ग्रहा स्पेस, कॉस्मोसर्व, जर्मनी की डीक्यूबेड और खुद स्काईरूट के टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन पेलोड शामिल थे। यह इस बात का सबूत है कि भारत की प्राइवेट लॉन्च क्षमता को ऐसे ग्राहक भी परख रहे हैं, जिनके पास दुनिया में कहीं भी जाने का विकल्प था।‘

भारत के स्पेस सेक्टर में पॉलिसी सुधारों की वजह से देश में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2022 में एक से बढ़कर 2024 तक लगभग 200 हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, इस सेक्टर ने 2023 के सिर्फ आठ महीनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया।

मीडिया हाउस ने बताया कि पॉलिसी बनाने वाले 2021 में ग्लोबल स्पेस इकॉनमी में भारत की हिस्सेदारी को लगभग 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक 8 प्रतिशत और 2047 तक 15 प्रतिशत करने की योजना बना रहे हैं, और विक्रम-1 यह साबित करता है कि इसके लिए जरूरी इंडस्ट्रियल बेस असल में मौजूद है।

ट्रंप के नए टैरिफ का अमेरिका को दवाएं आपूर्ति करने वाली भारतीय फार्मा कंपनियों पर असर बेहद सीमित रहेगा: एनालिस्ट

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जेनेरिक दवाओं पर लगाए गए नए टैरिफ का अमेरिकी बाजार में दवाओं की आपूर्ति करने वाली भारतीय फार्मा कंपनियों पर बहुत कम असर पड़ेगा, क्योंकि ये 2028 से लागू होने वाले हैं। यह जानकारी एनालिस्ट की ओर से बुधवार को दी गई।

कई भारतीय फार्मा कंपनियों की अमेरिका में सहायक कंपनियां हैं। साथ ही, भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले उत्पादों के ट्रांसफर प्राइस और अमेरिकी बाजार में उनकी अंतिम बिक्री कीमत में काफी अंतर होता है। माना जा रहा है कि टैरिफ उस कीमत पर लगाया जाएगा, जिस पर उत्पाद अमेरिकी बाजार में प्रवेश करता है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के एसवीपी एवं इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एनालिस्ट (हेल्थकेयर) तुषार मनुधाने ने कहा, ‘अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली करीब 90 प्रतिशत जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन दवाएं आयात की जाती हैं। ऐसे में जब भी यह टैरिफ लागू होगा, इसका असर अमेरिका को दवाएं निर्यात करने वाले सभी देशों पर होगा, यह केवल भारत तक सीमित नहीं है।‘

उन्होंने कहा, ‘भारत जैसे देशों को आउटसोर्सिंग का मुख्य कारण यह है कि यहां दवाओं के निर्माण की लागत अमेरिका की तुलना में 40 से 60 प्रतिशत कम है। टैरिफ लागू होने के बाद भी भारत की कम लागत पर उत्पादन करने की यह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पूरी तरह खत्म नहीं होगी। मनुधाने ने बताया कि यदि अमेरिका में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित भी किया जाता है, तो उसे तैयार होने में कम से कम दो वर्ष लगेंगे। इसके बाद प्लांट का निरीक्षण और उत्पादों की मंजूरी (प्रोडक्ट अप्रूवल) की प्रक्रिया में भी कम से कम 12 से 15 महीने का समय लगेगा। इससे नए प्रतिस्पर्धियों के बाजार में आने में और अधिक देरी होगी।

उन्होंने कहा कि इन सभी कारणों से अमेरिका में जेनेरिक दवाओं के निर्माण संयंत्र स्थापित करने की आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठते हैं। इसलिए अमेरिकी बाजार में दवाओं की आपूर्ति करने वाली भारतीय फार्मा कंपनियों पर इसका प्रभाव बेहद सीमित रहने की संभावना है।

भारत को अकसर ‘दुनिया की फार्मेसी’ कहा जाता है, क्योंकि वह दुनिया के अनेक देशों को जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है।

अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं में मात्रा के आधार पर भारतीय दवाओं की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 9.7 अरब डॉलर मूल्य की दवाओं का निर्यात किया, जो उसके कुल 25.8 अरब डॉलर के वैश्विक फार्मा निर्यात का 38 प्रतिशत था।

राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से आयातित जेनेरिक दवाओं को दो वर्षों तक टैरिफ से छूट मिलेगी। इसके बाद इन पर पहले 100 प्रतिशत और फिर 200 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जाएगा।

तनावमुक्त जीवन और बेहतर एकाग्रता के लिए करें उत्थित पार्श्वकोणासन योगासन

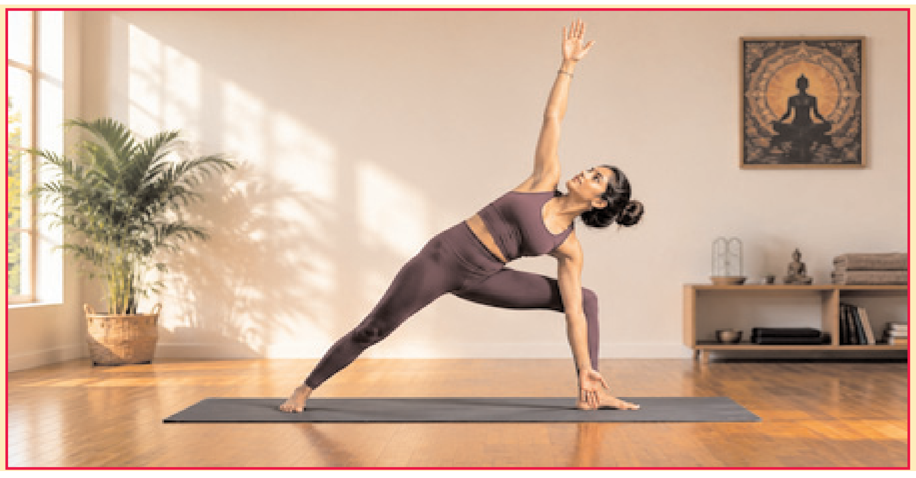

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली। आज की व्यस्त जीवनशैली में शारीरिक संतुलन और आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखना एक चुनौती बन गया है। ऐसी स्थिति में उत्थित पार्श्वकोणासन एक ऐसा योगासन है, जो शरीर को ताजगी प्रदान करता है।

उत्थित का अर्थ है, खिंचाव, पार्श्व का अर्थ बगल और कोण का अर्थ एंगल हैं। यह एक ऐसा आसन है जिसमें शरीर के पार्श्व (साइड) भाग में एक संपूर्ण और सुंदर पार्श्व-कोण बनता है। यह न केवल हमारी शारीरिक शक्ति और लचीलेपन को बढ़ाता है, बल्कि मन में स्थिरता और एकाग्रता भी लाता है।

आयुष मंत्रालय के अनुसार, उत्थित पार्श्वकोणासन (विस्तारित पार्श्व कोण मुद्रा) खड़े होकर किए जाने वाले योगासनों में से एक सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक आसन है, जो पेट के अंगों की मालिश करता है, पाचन में सुधार लाता है, और पैरों व रीढ़ को मजबूत करता है। इसके अलावा, शरीर में लचीलापन भी बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही, यह छाती के विकास और साइटिका के दर्द में राहत दिलाता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति साइटिका से ज्यादा परेशान है, तो वे सबसे पहले डॉक्टर से सलाह करें।

इसको करना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले योगा मैट पर दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर फैला लें। अब दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुटने से धीरे-धीरे मोड़ें और उसी मुद्रा में नीचे की ओर बैठें।

फिर अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के पास जमीन पर रखें और बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा 90 डिग्री के एंगल में रखने की कोशिश करें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहने की कोशिश करें, फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। हालांकि, शुरुआती अभ्यासकर्ताओं को इसको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आदत हो जाएगी और शरीर खुलने लगेगा। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ (बाएं पैर को मोड़कर) दोहराएं।

गंभीर पीठ या गर्दन की चोट, उच्च/निम्न रक्तचाप, और माइग्रेन की स्थिति में इस आसन का अभ्यास करने से बचें।

इको-फ्रेंडली प्लास्टिक पैकेजिंग से बढ़ेगी खाने की शेल्फ लाइफ, घटेगा प्रदूषण

विश्व केसरी ■

नई दिल्ली । आज के समय में खाने-पीने की चीजों को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखने में फूड पैकेजिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। दूध, फल, सब्जियां, स्नैक्स या तैयार भोजन हर चीज को ऐसी पैकेजिंग की जरूरत होती है जो हवा और नमी से बचाकर उसकी गुणवत्ता बनाए रखे। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। यह वर्षों तक मिट्टी और पानी में पड़ा रहता है और आसानी से नष्ट नहीं होता। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जो भोजन को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाएं।

इसी दिशा में इंडोनेशिया के हसनुद्दीन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंडी दिरपान और उनकी टीम ने एक नई तरह की बायोडिग्रेडेबल फूड पैकेजिंग फिल्म तैयार की है। यह फिल्म पौधों से बनने वाले प्लास्टिक पॉलीलैक्टिक एसिड (पीएलए) पर आधारित है। खास बात यह है कि इसमें मजबूती बढ़ाने के लिए माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज (एमसीसी) और ऑक्सीजन को नियंत्रित करने के लिए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सीटोल्यून (बीएचटी) का इस्तेमाल किया गया है। इस शोध को 5 मई 2026 को ऑनलाइन प्रकाशित किया गया और मार्च 2027 में आसियान जर्नल फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन मैटेरियल्स के वॉल्यूम 6 में प्रकाशित किया जाएगा।

सामान्य तौर पर पीएलए को पर्यावरण-अनुकूल प्लास्टिक माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक स्रोतों से बनता है और समय के साथ नष्ट भी हो जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सामान्य प्लास्टिक जितना मजबूत नहीं होता और ऑक्सीजन को भी उतनी अच्छी तरह नहीं रोक पाता। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खाने की चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं। इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसा तरीका खोज रहे थे जिससे पीएलए की मजबूती भी बढ़े और वह ऑक्सीजन को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके।

इस शोध का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें प्रयुक्त सेल्यूलोज को लकड़ी या पारंपरिक फसलों के बजाय, फर्मेंटेड (किण्वित) नारियल पानी से तैयार किया गया है। यह वही प्रक्रिया है, जिसके ज़रिए ‘नाटा डी कोको’ नामक जेलीनुमा खाद्य पदार्थ बनाया जाता है।

इस प्रक्रिया के दौरान बैक्टीरिया पूरी तरह शुद्ध और रेशेदार सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस सेल्यूलोज को परिष्कृत (साफ) करके ‘माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज’ (एमसीसी) पाउडर में बदला और फिर इसे पीएलए फिल्म में मिलाया।

बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप बढ़ा, ‘वैक्सीनेशन गैप’ बड़ी वजह

विश्व केसरी ■

ढाका । बांग्लादेश में खसरे ने कई मासूमों की जान ले ली है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, देश में हर दिन औसतन करीब 4 बच्चों की मौत हो रही है और 800 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इस बीच, सरकार और आम लोगों का ध्यान इस स्वास्थ्य संकट से कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में खसरे के लगातार बढ़ते प्रकोप का अहम कारण ‘वैक्सीनेशन गैप’ को बताया जा रहा है।

सरकार के इस दावे के बावजूद कि उसने आपातकालीन खसरा टीकाकरण अभियान का लक्ष्य पार कर लिया है, अस्पतालों में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें टीका नहीं लगाया गया है। इससे टीकाकरण कवरेज में मौजूद कमियों का पता चलता है।

जुलाई के पहले तीन हफ्तों में खसरे का प्रकोप गंभीर बना रहा। बांग्लादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान हर दिन औसतन 1,005 संदिग्ध और लैब टेस्ट से कन्फर्म किए गए खसरे के मामले सामने आए, 821 अस्पताल में भर्ती किए गए और रोजाना करीब 4 बच्चों की मौत दर्ज की गई।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ‘द डेली स्टार’ ने खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सत्यापन समिति के अध्यक्ष महमूदुर रहमान के हवाले से कहा, ‘स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन टीकाकरण अभियान के दो महीने बाद भी यह अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। ऐसा लगता है कि अधिकारी इस स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।‘

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, खसरे का प्रकोप लगातार जारी रहने के पीछे करीब 40 लाख बच्चों का टीकाकरण से वंचित रह जाना, अभियान के निर्धारित आयु वर्ग से बाहर के बच्चों में संक्रमण फैलना और संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों की कमजोरी प्रमुख कारण हैं।

बांग्लादेश में मंगलवार को खसरे के प्रकोप से कम से कम चार बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही, 15 मार्च से अब तक इस बीमारी से जुड़ी कन्फर्म और खसरे जैसे लक्षणों की वजह से (संदिग्ध श्रेणी में रखी गई) 797 मासूमों की मौत हो चुकी है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, ये आकंड़ा मंगलवार (पिछले 24 घंटों) सुबह 8 बजे तक का है। हाल ही में हुई मासूमों की मौत को बीमारी से जुड़ी संदिग्ध मौत के रूप में चिन्हित किया गया है।

‘ड्रग फ्री गुजरात’ अभियान को मजबूती, सभी जिला अस्पतालों में खुलेंगे नशा मुक्ति केंद्र, 14.90 करोड़ मंजूर

विश्व केसरी ■

गांधीनगर । गुजरात सरकार ने राज्य को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 14.90 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस राशि से राज्य के सभी 34 जिला अस्पतालों में 15-15 बेड वाले नशा मुक्ति केंद्र (डी-एडिक्शन सेंटर) स्थापित किए जाएंगे।

राज्य सरकार के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उनके अपने जिले में ही बेहतर इलाज और पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े।

हर जिला अस्पताल में बनने वाले इन केंद्रों में वैज्ञानिक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन, नशा मुक्ति उपचार, काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, पारिवारिक परामर्श और पुनर्वास (रीहैबिलिटेशन) जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इन केंद्रों में ओपीडी और आईपीडी दोनों तरह की सेवाएं दी जाएंगी। सरकार ने बताया कि यहां डॉक्टरों, नर्सों, काउंसलरों, मनोवैज्ञानिकों और अन्य प्रशिक्षित विशेषज्ञों की बहु-विषयक टीम मरीजों को एकीकृत और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी।

सरकार का कहना है कि इन केंद्रों के जरिए नशे की लत से जूझ रहे लोगों को केवल चिकित्सा ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक सहयोग भी मिलेगा। इससे मरीजों के साथ-साथ उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक और भावनात्मक बोझ भी कम होगा।

तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, 13 सरकारी संस्थानों में नर्सिंग की 855 नई सीटें बढ़ेंगी

विश्व केसरी ■

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नर्सिंग शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी नर्सिंग संस्थानों में सीटों की संख्या 796 से बढ़ाकर 1,651 करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों में कुल 855 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित नर्सिंग पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए किफायती नर्सिंग शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह विस्तार सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस सीटों के साथ-साथ एलाइड हेल्थ एजुकेशन को भी मजबूत किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (डीएमई एंड आर) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आवश्यक नियामकीय स्वीकृतियां मिलने के बाद नई सीटों पर प्रवेश शुरू किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार, 13 सरकारी संस्थानों में 660 बीएससी नर्सिंग, 120 पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और 75 एमएससी नर्सिंग की नई सीटें जोड़ी जाएंगी। बीएससी नर्सिंग की कुल सीटें 510 से बढ़कर 1,170 हो जाएंगी। इनमें अधिकांश नई सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसरों में बन रहे छह नए मॉडल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक संस्थान का निर्माण लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है, जिसके लिए तमिलनाडु डॉ. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अलावा कोयंबटूर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ईएसआई एंड हॉस्पिटल में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। प्रस्तावित सीट आवंटन के अनुसार, तिरुचिरापल्ली के केएपी विश्वनाथन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तथा तिरुवन्नामलाई, वेल्लोर, धर्मपुरी, इरोड और तिरुनेलवेली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की 100-100 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी।

विश्व केसरी

वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप: अनाहत और आर्यवीर ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

विश्व केसरी

ओंटारियो। भारत के युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह और आर्यवीर दीवान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने-अपने मुकाबलों में सीधे गेम में जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया।

महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में हांगकांग की पुई यिन चोले लो को आसानी से 11-3, 11-1, 11-3 से हराया। अब उनका सामना मलेशिया की 13/16 सीड डोयस ये सैन ली से होगा। अनाहत इस टूर्नामेंट में भारत की पहली जूनियर विश्व चैंपियन बनने के लक्ष्य के साथ उतरी हैं।

पुरुष वर्ग में 5/8 सीड आर्यवीर दीवान ने भी शानदार खेल दिखाया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के जोसेफ फीस्ट को सीधे गेम में 11-4, 11-3, 11-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब आर्यवीर का मुकाबला अमेरिका के 9/12 सीड यासीन शालाबी से होगा। हालांकि, कुछ भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना भी करना पड़ा। गुरवीर सिंह, युशा नफीस, सान्वी कलंकी, रुद्र सिंह और अनिका दुबे अपने से बेहतर रैंकिंग वाले खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबले हार गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए।

दूसरे दिन के मुकाबलों में कई रोमांचक नतीजे भी देखने को मिले। ब्राजील की लॉरा सिल्वा ने 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 3-2 से अपने नाम किया और अंतिम 16 में जगह बनाई।

मलेशिया की हरलीन टैन ने भी कनाडा की विंग काई ग्लेडिस हो के खिलाफ 2-1 से पीछे रहने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए जीत दर्ज की। इसके अलावा, इंग्लैंड के डायलन रॉबर्ट्स, हांगकांग की हेलेन टैंग, सऊदी अरब के मोहम्मद अलनासफान और मिस्र की हबीबा रिज्क ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। बेल्जियम की सवाना मोक्सहम ने भारत की सान्वी कलंकी को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई।

राउंड ऑफ 32 के नतीजे:

पुरुष: 5/8-आर्यवीर दीवान ने जोसेफ फीस्ट (साउथ अफ्रीका) को 11-4, 11-3, 11-3 से हराया; 2-एडम हवल (इजरायल) ने गुरवीर सिंह को 11-6, 11-8, 11-3 से हराया; 5/8-निखिलेश्वर मोगनसुंदरम ने युशा नफीस को 11-9, 11-7, 11-8 से हराया।

महिलाएं: 5/8-सवाना मोक्सहम (बेल्जियम) ने सान्वी कलंकी को 11-7, 11-4, 11-2 से हराया; 3/4-बार्ब समेह (इजरायल) ने रुद्र सिंह को 11-5, 11-6, 11-1 से हराया; त्स चिंग चेउंग (हांगकांग) ने अनिका दुबे को 11-6, 11-7, 11-5 से हराया; 1-अनाहत सिंह ने पुई यिन चोले लो (हांगकांग) को 11-3, 11-1, 11-3 से हराया।

हेटमायर-रदरफोर्ड ने खेली आतिशी पारी, वेस्टइंडीज ने पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड को 2 विकेट से हराया

विश्व केसरी

बारबाडोस । वेस्टइंडीज ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को पांचवें वनडे मुकाबले में 2 विकेट से हराया। केंसिंग्टन ओवल के मैदान पर न्यूजीलैंड से मिले 269 रनों के लक्ष्य को कैरेबियाई टीम ने 47.3 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल किया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी रही, और अकीम ऑगस्टे और जस्टिन ग्रीव्स ने पहले विकेट के लिए 57 रन जोड़े।

ग्रीव्स ने 15 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के की मदद से 22 रन बनाए। वहीं, ऑगस्टे ने 24 गेंदों में 34 रन बनाए। कीसी कार्टि अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और वह 20 रन बनाकर आउट हुए। शाई होप ने कुछ दमदार शॉट्स लगाए और वह 52 गेंदों में 39 रन बनाने के बाद जेडन लेनोक्स का शिकार बने।

123 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद लड़खड़ाती दिख रही वेस्टइंडीज की पारी को शेरफेन रदरफोर्ड और शिमरॉन हेटमायर ने संभाला। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 90 गेंदों में 95 रन जोड़े। रदरफोर्ड ने 64 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए। वहीं, हेटमायर 64 गेंदों में 69 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे। हेटमायर ने अपनी इस पारी में 2 चौके और 4 छक्के लगाए।

गेंदबाजी में न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी और लेनोक्स ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

इससे पहले, न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 268 रन बनाए। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और हेनरी निकोल्स महज 10 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, इसके बाद विल यंग और निक केली ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 86 रन जोड़े। यंग ने 63 गेंदों में 56 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके और एक छक्के लगाया। वहीं, केली ने 80 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन बनाए।

मार्क चैपमैन 11 रन ही बना सके। टॉम लाथम अच्छी लय में दिखाई दिए और उन्होंने 71 गेंदों में 6 चौके और एक छक्के की मदद से 69 रनों का योगदान दिया। गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की तरफ से 19 वर्षीय गेंदबाज विटेल लॉव्स और अल्जारी जोसेफ ने दो-दो विकेट अपने नाम किए। हालांकि, पांचवें वनडे में मिली हार के बावजूद न्यूजीलैंड सीरीज को 3-2 से अपने नाम करने में सफल रही।

असम प्रीमियर लीग राज्य की प्रतिभाओं के लिए एक लॉन्चपैड है: अबू नेचिम

विश्व केसरी

गुवाहाटी । पूर्व तेज गेंदबाज अबू नेचिम ने असम प्रीमियर लीग (एपीएल) को राज्य के उभरते क्रिकेटरों के लिए एक जरूरी लॉन्चपैड बताया है। उन्होंने कहा कि एपीएल राज्य की स्थानीय प्रतिभाओं को जरूरी पहचान देगा।

नेचिम ने बुधवार को टूर्नामेंट की तरफ से जारी एक बयान में कहा, 'असम प्रीमियर लीग बहुत जरूरी है, यह हमारे जूनियर्स के लिए सच में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। नीलामी में हमारे 270 से ज्यादा खिलाड़ी थे, और मुझे उनमें से सिर्फ 120 के बारे में ही पता था। इससे पता चलता है कि पूरे असम में कितने अनदेखे टैलेंट है। लीग उन सभी खिलाड़ियों को एक मंच देती है जहां उन्हें देखा जा सकता है।

नेचिम 2006 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए खेले थे और असम के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने के अलावा, उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस (2010-2013) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2014-2016) के साथ भी खेला है।

टॉप-फलाइट क्रिकेट में अपने सफर और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और बैटिंग ऑल-राउंडर रियान पराग के आगे बढ़ने से तुलना करते हुए, नेचिम, जो गुवाहाटी रॉयल्स के सेट-अप का हिस्सा हैं, ने बताया कि यह टूर्नामेंट स्टेट-लेवल क्रिकेट और एलीट प्लेटफॉर्म के बीच के अंतर को कम करता है।

उन्होंने कहा, 'हर खिलाड़ी और हर फ्रेंचाइजी का मकसद टूर्नामेंट जीतना होता है। एपीएल के खिलाड़ी अगले साल आईपीएल या भारत के लिए भी खेल सकते हैं। यही असली मौका है, जो यह लीग देती है, और यह आने वाले कई सालों तक असम क्रिकेट के काम आएगा। असम क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) के तहत 'आमार एक्सोम, आमार गौरब' (हमारा असम, हमारा गर्व) के आधिकारिक मोटो के साथ आयोजित एपीएल में पूरे राज्य की आठ फ्रेंचाइजी टीमें शामिल हैं। टूर्नामेंट के पहले एडिशन के मैच स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव दिखाए जाएंगे और जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम किए जाएंगे।

फॉर्म में उतार-चढ़ाव क्रिकेट का हिस्सा, टीम के लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहता हूं: वैभव सूर्यवंशी

विश्व केसरी

हरारे । भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज में हरारे में 23 जुलाई से शुरू होगी। इस सीरीज में एक बार फिर से सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर नजर रहेगी, जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में लगातार तीन मैचों में असफल रहे थे। वैभव भी इस सीरीज में अपनी फॉर्म पाने और बड़ी पारी खेलने की चाहत रखते हैं।

वैभव ने कहा है कि पिछले चार महीनों में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं। यह क्रिकेट का हिस्सा है, ऐसा होता रहेगा। मुझे प्रक्रिया को फॉलो करना होगा और टीम के लिए अपना सौ प्रतिशत देना होगा।

बीसीसीआई टीवी पर साझा एक वीडियो में सूर्यवंशी ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए (मार्गदर्शन वगैरह), कोच मुझे दे रहे हैं और मुझे जो भी अभ्यास चाहिए, वह मुझे मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मविश्वास भी है।

सूर्यवंशी ने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत यादगार ग्राउंड है। सिर्फ चार महीने पहले, हमने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था और जीता था, इसलिए यह बहुत खास ग्राउंड है। यहां वापस आकर सच में बहुत मजा आ रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व करना हर किसी का सपना होता है। यह बहुत खास पल होता है।

सूर्यवंशी ने हाल ही में अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में इसी ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन की पारी खेल भारत को जीत दिलायी थी।

हरारे की पिच के बारे में सूर्यवंशी ने कहा, 'यहां की पिच और कंडीशन के बारे में मुझे काफी आइडिया है। मैं पिछले अंडर-19 वर्ल्ड कप के दौरान यहां खेला था। मैंने उस टूर्नामेंट के दौरान जो कुछ भी सीखा है, उसे अब मैचों के दौरान इस्तेमाल करने और अच्छा करने की कोशिश करूंगा।

उन्होंने कहा, 'मैं अपने अभ्यास पर भरोसा करूंगा जो मैंने अब तक की है और अपने गेम पर भरोसा करने की कोशिश करूंगा और टीम के लिए जो भी योगदान दे सकता हूं।

आईसीसी वनडे रैंकिंग: डेरिल मिशेल के करीब पहुंचे शुभमन गिल, जो रूट की टॉप-10 में एंट्री

विश्व केसरी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा बुधवार को जारी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल नंबर वन बल्लेबाज बनने के काफी करीब आ गए हैं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को भी काफी फायदा हुआ है।

आईसीसी की ताजा रैंकिंग में न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेरिल मिशेल 802 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं। गिल और मिशेल की रेटिंग में सिर्फ एक अंक का अंतर है। विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं, जबकि लॉर्ड्स में हाल ही में 138 रन की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान पांचवें स्थान पर हैं।

पाकिस्तान के बाबर आजम और आयरलैंड के हैरी टैक्टर को 1-1 स्थान का फायदा हुआ है। दोनों क्रमश: छठे और सातवें स्थान पर हैं। भारत के खिलाफ संपन्न वनडे सीरीज में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे इंग्लैंड के जो रूट को 4 स्थान का फायदा हुआ है। रूट शीर्ष 10 खिलाड़ियों में वापस आ गए हैं और आठवें नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज के शे होप को तीन स्थान का घाटा हुआ है, वे नौवें नंबर पर हैं। श्रीलंका के चरिथ असलांका एक अंक के नुकसान के बावजूद दसवें स्थान पर हैं।

वनडे फॉर्मेट के शीर्ष दस गेंदबाजों की बात करें तो अफगानिस्तान के राशिद खान पहले और पाकिस्तान के अबरार अहमद दूसरे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को एक स्थान का फायदा हुआ है, वह तीसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटनर को तीन स्थान का फायदा हुआ है। सेंटनर चौथे स्थान पर हैं।

दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज और श्रीलंका के महिश तिक्षाणा क्रमश: पांचवें और छठे स्थान पर हैं। दोनों को एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी दो स्थान के फायदे के साथ सातवें और बांग्लादेश के मेहदी हसन दो स्थान के फायदे के साथ आठवें स्थान पर हैं।

यूटीटी सीजन 7: कोलकाता थंडरब्लेड्स ने यू मुंबा को हराया, सेमीफाइनल में पहुंचीं दोनों टीमें

विश्व केसरी

पणजी (गोवा)। अल्टीमेट टेबल टेनिस (यूटीटी) सीजन 7 में मंगलवार को एक रोमांचक मुकाबले में एचवीआर कोलकाता थंडरब्लेड्स ने यू मुंबा टीटी की जीत का सिलसिला तोड़ते हुए 8-7 से जीत हासिल की। पणजी के पास तलेइगाओ में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हार के बावजूद, यू मुंबा ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। उनके बेहतर गेम काउंट और अनुकूल समीकरणों ने कोलकाता और लीग में सबसे आगे चल रही डेंपो गोवा चैलेंजर्स के साथ उनके क्वालिफिकेशन को सुनिश्चित किया।

कोलकाता की युवा खिलाड़ी तनीषा कोटेचा ने अन्ना हर्सी को इस सीजन की पहली हार का स्वाद चखाकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि जेंग जियान ने आखिरी मैच के निर्णायक गेम में संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की। ? ?इस नतीजे ने लीग के आखिरी दो मुकाबलों से पहले ही दोनों टीमों का नॉकआउट स्टेज में पहुंचना तय कर दिया, जिससे अब केवल एक जगह खाली बची है।

कोलकाता ने एडुआर्ड आयोनेस्कु के जरिए अच्छी शुरुआत की; उन्होंने एक गेम हारने के बाद वापसी करते हुए मानुष शाह को 9-11, 11-8, 11-7 से हराया। इसके बाद तनीषा कोटेचा ने सीजन का एक बड़ा उलटफेर करते हुए अब तक अजेय रहीं अन्ना हर्से को सीधे गेम में 11-6, 11-4, 11-4 से हराकर शानदार जीत दर्ज की।

यू मुंबा ने मिक्स्ड डबल्स में वापसी की; मानुष और हर्सी ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद अंकुर भट्टाचार्जी और तनीषा को तीन गेम में 8-11, 11-4, 11-7 से हराकर डिफेंडिंग चैंपियंस को मुकाबले में बनाए रखा।

इसके बाद फ्रांस के लिलियन बार्डेट ने एक और कड़े मुकाबले में अंकुर को तीन गेम में 11-9, 11-8, 6-11 से हराकर यू मुंबा को जीत के करीब पहुंचाया। हालांकि, नित्याश्री मणि ने शुरुआती दो गेम में जियान को 11-10, 11-5 से हराकर मुकाबला 7-7 से बराबर कर दिया।

इसके बाद सब कुछ निर्णायक अंतिम गेम पर आ टिका। दबाव के बीच जियान ने शानदार वापसी करते हुए 11-5 से जीत दर्ज की और कोलकाता को मुकाबला जिता दिया। इस नतीजे के साथ दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली।

जयडेन लेनोक्स के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, कुंबले-वॉर्न और अफरीदी को छोड़ा पीछे

विश्व केसरी

नई दिल्ली। पांचवें वनडे में मिली हार के बावजूद न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज को 3-2 से अपने नाम करने में सफल रही। टीम की इस जीत में गेंद से अहम भूमिका जयडेन लेनोक्स ने निभाई। उन्होंने सीरीज में कुल 14 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी चुना गया।

लेनोक्स की घूमती गेंदों के आगे पूरी सीरीज में कैरेबियाई बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। लेनोक्स ने 5 मुकाबलों में 14 विकेट लेने के साथ ही खास उपलब्धि को भी अपने नाम किया है। वह एक द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिनर्स की लिस्ट में पूर्व दिग्गज गेंदबाज शेन वॉर्न, शाहिद अफरीदी और अनिल कुंबले से आगे निकल गए हैं। इन तीनों पूर्व खिलाड़ियों के नाम एक सीरीज में 13 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। लेनोक्स ने अकिला धनंजय की बराबरी कर ली है। धनंजय ने साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज में 14 विकेट चटकाए थे।

एक द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व गेंदबाज अमित मिश्रा के नाम है, जिन्होंने 18 विकेट चटकाए हैं। वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कुलदीप यादव का नाम है, जो एक वनडे सीरीज में 17 विकेट निकाल चुके हैं। जयडेन लेनोक्स का प्रदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पांचवें एकदिवसीय मुकाबले में भी शानदार रहा। उन्होंने 9 ओवर के स्पेल में महज 35 रन खर्च करते हुए 3 विकेट चटकाए।

पांचवें वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 268 रन लगाए। टीम की ओर से विल यंग (56 रन), निक केरी (64 रन) और टॉम लाथम (69 रन) ने अर्धशतकीय पारी खेली।

इसके जवाब में कैरेबियाई टीम ने शेरफेन रदरफोर्ड द्वारा खेली गई 61 और शिमरोन हेटमायर की 69 रनों की नाबाद पारी के बूते 269 रनों के लक्ष्य को 47.3 ओवर में हासिल किया।

स्वात्वधिकारी राइवल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुजीत कुमार द्वारा साई प्रीटिंग प्रेस, डी-85, सेक्टर 6 नोएडा,गौतम बुध्द नगर पिन कोड -201301 उ.प्र. से मुद्रित और मकान संख्या एन-58 जगतराम पार्क के सामने, लक्ष्मी नगर पूर्व दिल्ली-110053 से प्रकाशित
समाचार संपादक : चन्द्रमणी साव (पीआरबी एक्ट के अनुसार समाचार पत्र चयन एवं संपादन के लिए उत्तरदायी। नोट किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा) मोबाइल 9340573892 ई-मेल: vishwakesari2026@gmail.com,आर.एन.आई.नं. DLHIN/2015/61415